वर्ष-7 अंक-4 अप्रैल 2017 मूल्य 15

लोक जागृति

पत्रिका

कानूनी मुद्दों पर मुखर बातचीत एवं सामाजिक जन जागरण का मासिक प्रकाशन

यूपी में योगी राज

OUR SERVICES:
- Anti Ageing Treatment
- Botox
- Fillers
- Acne Scars
- Birth Marks
- Frown Lines
- Keloid
- Laser Hair Removal
- Moles
- Pigmentation
- Skin Rejuvenation
- Skin Tag
- Tattoo Marks
- Vitiligo (Leucoderma)
- Warts
- Wrinkles
- Whitening Peels

16th ANNIVERSARY

TRANSFORM YOUR BODY WITHOUT SURGERY OR DOWNTIME

DR. T. A. RANA
MBBS, MD (Dermatology)
Dermatologist and Aesthetic Laser surgeon
www.ranaskinlaser.com

Skin Laser Institute
CARE WITH SATISFACTION
A-50, Sector-26, opp. Kailash Hospital, Noida-201301, Contact: 0120-2443400, 7838976117, 9811309751

बीसीआई के खिलाफ लामबंद हुए वकील

संबंधित खबर पेज 29 पर

लोक जागृति के 20 प्रमुख मिशन

1.बेरोजगारों को रोजगार पाने में सहयोग
2.जन साधारण को स्वास्थ सेवाओं में जागरुकता एवं सहयोग
3.आरक्षण आर्थिक आधार पर होवे न कि जाति धर्म के आधार पर
4.पुलिस व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन
5.सरकारी सेवा के कर्मचारियों अधिकारियों को भी कार्य मूल्यांकन के आधार पर ही पदोन्नति एवं वेतन बढ़ोत्तरी हो न कि मात्र समयबद्ध
6.न्यायालयों के लिए हर प्रकार के मामलों के निस्तारण का समय तय हो
7.न्यायालयों में भारतीय भाषाओं में भी काम हो।
8.संसद एवं विधान सभाओं में चुने सदस्य राजनीति नहीं राष्ट्रनीति पर काम करें
9.शिक्षण एवं चिकित्सा संस्थानों की व्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण हो
10.सामाजिक सोसिएल ऑडिट की व्यवस्था हो
11.सक्षम नागरिकों को किसी तरह की सब्सिडी न मिले
12.रु. 2000 के नोटों का चलन बन्द हो ताकि ब्लैकमनी का चलन रुके
13.हर वस्तु एवं सेवा की लागत का अंकेक्षण करना और उपभेक्ता को लागत मूल्य की जानकारी
14.भारतीय दण्ड संहिता एवं साक्ष्य संहिता में मूल परिवर्तन कर झूठे केस एवं झूठी गवाही या गवाही बदलने, मुकरने पर दंडात्मक कार्यवाही का प्रावधान
15.समान शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था
16.देश के प्राकृतिक संसाधनों पर सरकार का पूर्ण अधिकार
17.शहरी आवासीय भूमि पर भी ग्रामीण कृषि भूमि की तरह सीलिंग कानून
18.कराधान एवं लाइसेंसी प्रक्रिया को सरल एवं स्पष्ट करना
19.लालफीताशाही का सर्वनाश करना
20.गरीबों की सही पहचान कर उन्हें निःशुल्क सेवा या सब्सिडी की जगह उचित रोजगार एवं स्वावलम्बी बनाकर राष्ट्रनिर्माण में शामिल करना।

हमारा निस्वार्थ प्रयास

लोक जागृति की स्थापना स्वामी नारायण जी के विचारों से प्रेरित होकर की गई है। योगी, त्यागी, सन्यासी महापुरूष लोक की जागृति के लिए संन्यास लेते हैं जिनमें स्वामी नारायण जी एक प्रमुख नाम है। स्वामी जी ने मानवतावादी धर्म के प्रसार–प्रचार के लिए विश्व भर में प्रयत्न किया और उनके प्रयास सफल रहे। वे वसुधैव कुटुम्बकम् की वैदीय परम्परा के प्रसारक योगी रहे। उनके धर्म–कर्म, मानवता के प्रसारक शिक्षा केन्द्र अक्षरधाम के नाम से पूरे विश्व में जगह जगह स्थापित हुए। उन्हीं सैंकड़ों मंदिरों में से एक, दिल्ली में स्थित अक्षरधाम मंदिर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है स्वामी नारायण जी ने जिला गोंडा के छपिया में जन्म लिया था। लोकजागृति संस्था से जुड़े हम अधिकांश सदस्य उन्हीं के क्षेत्र में अपना बालकाल और छात्रजीवन जिये और उनके बारे में सुनते पढ़ते रहे। कुछ सामर्थ्य मिलने पर उनके पगचिह्नों पर चलकर यथा संभव मानवतावादी, जनहितैषी काम करने की इच्छा थी जिसके प्रयोग और प्रयास में कुछ सुधी, पाठकों, विज्ञ जनों के साथ मिलकर सन् 2010 में लोकजागृति की स्थापना की। अपनी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक क्षमतानुसार हम सभी सदस्य इस गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) के जरिये जनहितैषी प्रयास करते हैं और आम आदमी के सामाजिक, कानूनी मुद्दों से जुड़ी बातें प्रकाशित करते हैं।

प्रकाशित पत्रिका गाँव के ग्राम प्रधानों, जरूरतमंदों और समदर्शी विचारों से जुड़े सुधी जनों को निःशुल्क भेजी जाती हैं। सदस्य ही नहीं, लेखक, पत्रकार संस्था को निःशुल्क, अवैतनिक सेवा देते हैं। जनहित वाले कई आलेख हम साभार अन्य प्रकाशनों से उद्धृत करने की गुस्ताखी भी करते हैं।लोकजागृति संस्था भारतीय आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12–ए एवं 80–जी के तहत मान्यता प्राप्त है। इससे संस्था एन.जी.ओ. प्रमाणित होने के साथ ही सुधी, संवेदनशील लोगों से संस्था को प्रदत्त दान, से उन दाताओं को आयकर में 50 फीसदी राशि की छूट मिला करती हैं ।

हम दावा नहीं कर सकते कि अपने प्रयत्नों से बहुत कुछ बदल देंगे मगर छोटे–छोटे प्रयासों से समाज के अंतर्मन में रचनात्मकता बने रहती है, जिसके लिए सभी को यत्न करना चाहिए। मानव सभ्यता इसकी गवाह है। कायाकल्प कर देने या फिजा ही बदल देने के दावे या तो राजनैतिक लोग करते हैं या बड़बोले। हम स्वामी नारायण जी एवं युगों से दुनिया में अवतरित हुए ऐसे ही महापुरुषों की तरह उनके पगचिह्नों पर चलने का बहुत विनम्रता से सिर्फ तनिक प्रयास मात्र करते हैं। 'नामुक्तः क्षीयते कर्मः कल्प कोटि शतैरपि' की अवधारण से हमें ऐसे कर्मों में जुटने की ताकत मिलती है। ईश्वर दया करें कि हम भी शूक्ष्म सहयोग इस आदि अनंत मानव श्रृंखला, जीव जन्तु एवं पर्यावरण के हित में कर पाऐं। संस्था के इस पारदर्शी मिशन से किसी भी तरह के सहयोग के लिए जाति धर्म से ऊपर, जो समविचार महानुभाव जुड़ना चाहते हों, उनका सहृदय स्वागत है।

लोक जागृति फोन: 9560522777; website: www.lokjagriti.

Suresh Pandey 9810514888

INDIAN/ FOREIGN BOOKS, JOURNALS,
NEW/OLD LAW BOKS,
BACK VOLUMES & SUBSCRIPTIONS SUPPLIER

SK

SK ACADEMIC PUBLISHING PVT. LTD.

E-252/4, West Vinod Nagar, Delhi - 110092
E- mail: suresh66pandey@gmail.com
pandeysureshk@gmail.com

आवश्यकता है

देशभर में संवाददाताओं, विज्ञापन दाताओं की हर खबर और तस्वीर का उचित मूल्य

संपर्क करें

लोक जागृति पत्रिका

95 ए, सेक्टर 3, वैशाली, गाजियाबाद, उ.प्र. 201010
lokjagriti@gmail.com, 9560522777

जब तक वह जमीन पर था...

जब तक वह जमीन पर था
कुर्सी बुरी थी
जा बैठा जब कुर्सी पर वह
जमीन बुरी हो गई।
उसकी नजर कुर्सी पर लगी थी
कुर्सी लग गयी थी
उसकी नजर को
उसको नजरबन्द करती है कुर्सी
जो औरों को
नजरबन्द करता है।
महज ढाँचा नहीं है
लोहे या काठ का
कद है कुर्सी
कुर्सी के मुताबिक वह
बड़ा है छोटा है
स्वाधीन है या अधीन है
खुश है या गमगीन है
कुर्सी में जज्ब होता जाता है
एक अदद आदमी।
फाइलें दबी रहती हैं
न्याय टाला जाता है
भूखों तक रोटी नहीं पहुँच पाती
नहीं मरीजों तक दवा
जिसने कोई जुर्म नहीं किया
उसे फाँसी दे दी जाती है
इस बीच
कुर्सी ही है
जो घूस और प्रजातन्त्र का
हिसाब रखती है।
कुर्सी खतरे में है तो प्रजातन्त्र
खतरे में है
कुर्सी खतरे में है तो देश खतरे में है
कुर्सी खतरे में है तो दुनिया खतरे में है
कुर्सी न बचे
तो भाड़ में जायें प्रजातन्त्र
देश और दुनिया।
खून के समन्दर पर सिक्के रखे हैं
सिक्कों पर रखी है कुर्सी
कुर्सी पर रखा हुआ
तानाशाह
एक बार फिर
कत्ले–आम का आदेश देता है।
अविचल रहती है कुर्सी
माँगों और शिकायतों के संसार में
आहों और आँसुओं के
संसार में अविचल रहती है कुर्सी
पायों में आग लगने तक।
मदहोश लुढ़ककर गिरता है वह
नाली में आँख खुलती है
जब नशे की तरह
कुर्सी उतर जाती है।
कुर्सी की महिमा
बखानने का
यह एक थोथा प्रयास है
चिपकने वालों से पूछिये
कुर्सी भूगोल है
कुर्सी इतिहास है।

भाग रही बचती बचती...

भाग रही है बचती बचती घिरी हुई है आग
देख भयावह स्वप्न रात में अक्सर जाती जाग !
भाग्य छिपा है अंधियारे में हुए न पीले हाथ
काट रही है भरी जवानी भारी मन के साथ !
उस पर रोज खोदता गंदा घर के पीछे काग
जब जब चले मंद पुरवाई सिसके उसकी प्रीत !
ढूँढ निकाला था श्यामू ने नथुनी में संगीत
पर सागर में डूब गया है उसका भी अनुराग !
कैसे भला कली मुस्काये करते भौंरे तंग
अपना अपना राग छेड़ते लगना चाहैं अंग !
ताके झाँकें कीट पतंगे बिन माली का बाग
अगल बगल की सखियाँ सारी खेल रही है रंग !
पर जीने की खातिर जुगुरी सोच रही है ढंग
बरस रहा अँखियों से सावन कैसे गाये फाग !

धीरज श्रीवास्तव

साफ – साफ

बेनामी संपत्ति पर, नोटिस की तामील
मायाजी के भाई पर, ठोंकी पहली कील!
देखो किस, किस को मिले, नोटिस पर कुहराम
बेनामी संपत्ति में, बड़े–बड़ों का नाम!
गठबंधन का ये गणित, समझ में कैसे आय
समीकरण कैसे बने, सबकी अपनी राय!
जनता सुनने के लिए, पीएम को तैयार
पांच दिवस बाकी बचे, क्या छापें अखबार?
कालेधन के सूरमा हो जाएंगे फेल
नोट पुराने गर मिले,सात साल की जेल!

देख लकीरें.....

अश्रु पड़े नयनों पर भारी,
देख लकीरें दुख की सारी,
कोई पहने सुख की माला,
गिनता कोई दुख का छाला,
अपने हाथ नहीं है कुछ भी,
भाग्य कर्म का खेल निराला,
कितने भी आगे बढ़ जायें,
विधि के आगे दुनिया हारी,
देख लकीरें
जग सरिता की अद्भुत धारा,
सबको मिलता नहीं किनारा,
संचय करते जान मधुर सब,
कुछ पाते मीठा कुछ खारा,
चलती नहीं यहाँ कुछ मन की,
नर हो चाहे या हो नारी,
देख लकीरें।
जाने कैसी थी मजबूरी,
तिनके जैसी थी बस दूरी
पार नहीं कर पाया ये मन,
उम्र गुजर गई यूँ ही पूरी,
मूक बनी निश्छलता से अब,
खड़ी ताकती राह बेचारी,
देख लकीरें

छाया त्रिपाठी ओझा

इधर भी गधे हैं, उधर भी गधे हैं

इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं
जिधर देखता हूं गधे ही गधे हैं
गधे हंस रहे आदमी रो रहा है
हिंदोस्तां में ये क्या हो रहा है
जवानी का आलम गधों के लिये है
ये रसिया ये बालम गधों के लिये है
ये दिल्ली ये पालम गधों के लिये है
ये संसार सालम गधों के लिये है
पिलाए जा साकी पिलाए जा डट के
तू व्हिस्की के मटके पे मटके
मैं दुनिया को अब भूलना चाहता हूं
गधों की तरह झूमना चाहता हूं
घोड़ों को मिलती नहीं घास देखो
गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश देखो
यहां आदमी की कहां कब बनी है
ये दुनिया गधों के लिये ही बनी है
जो गलियों में डोले वो कच्चा गधा है
जो कोठे पे बोले वो सच्चा गधा है
जो खेतों में दीखे वो फसली गधा है
जो माइक पे चीखे वो असली गधा है
मैं क्या बक गया हूं ये क्या कह गया हूं
नशे की पिनक में कहां बह गया हूं
मुझे माफ करना मैं भटका हुआ था
वो ठर्रा था भीतर जो अटका हुआ था

प्रकाश आदित्य

लोक जागृति पत्रिका

अप्रैल 2017 वर्ष 7 अंक 4

संरक्षक

कपिल सिंघल

डा. ए.जी. अग्रवाल

संपादक

संतोष कुमार मिश्रा (एडवोकेट)

वित्त सलाहकार एवं सह सम्पादक

नीरज बंसल

समाचार संपादक

बृजमोहन

संपादकीय सहयोगी

सुरेश पाण्डेय

विजय बहादुर सिंह

तेज सिंह यादव (एडवोकेट)

नरेन्द्र कुमार सक्सेना

गिरीश त्रिपाठी

एस.बी.एस. गौतम

सत्येंद्र श्रीवास्तव

अश्विनी मिश्रा (एडवोकेट)

आलोक सोलंकी

राहुल मिश्र

जगजीत सिंह

कृष्ण कुमार पाण्डेय (एडवोकेट)

राजेश कुमार मिश्र

कमल कांत त्रिपाठी (एडवोकेट)

तरुण गुप्ता (एडवोकेट)

पूनम सिंह (एडवोकेट)

शोभा चौधरी

अनिल कुमार शुक्ला

रजनीश कुमार पाण्डेय

महेन्द्र पाण्डेय (एडवोकेट)

प्रमोद उपाध्याय (एडवोकेट)

मार्केटिंग

दीपक गुप्ता

साज सज्जा

A.N.R. Creation

7827449997

मुद्रक प्रकाशक एवं संपादक
संतोष कुमार मिश्र
द्वारा आदर्श प्रिंटिंग हाउस बी 32 महिंद्रा इंक्लेव शास्त्री नगर गाजियाबाद से मुद्रित एवं 3ए 341 वैशाली, गाजियाबाद से प्रकाशित ।

इस पत्रिका में छपे किसी भी लेख से संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है । किसी भी विवाद के निराकरण के लिए गाजियाबाद न्यायालय पूर्ण क्षेत्राधिकार व निर्णय मान्य होगा ।

RNI NO.
UPHIN/2011/39809

सम्पादकीय

उत्तर प्रदेश एंव उत्तराखंड में जिस तरह बीजेपी प्रचण्ड बहुमत से जीती है उसके लिए मोदी जी एवं अमित शाह जी की रणनीति काबिले तारीफ है और जो जीता वही सिकन्दर होता है। लेकिन इस प्रचण्ड जीत की व्याख्या भी करने की जरुरत है, कि केंद्र की सरकार ने लोगों को क्या–क्या दे दिया जिससे लोगों ने लोकसभा के बाद विधानसभा में भी प्रचण्ड बहुमत दे दिया सिवाय नारा एवं भरोसा एवं वोटों के ध्रुवीकरण के अलावा। क्या लोगों को रोजगार मिला, क्या विदेशी काला धन आया, महंगाई कम हुई, किसानों की हालत सुधरी, क्या सांसद निधि का पैसा सांसदों द्वारा खर्च हो रहा है, सांसद लोग अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आखिर में लोगों ने इतनी जबरदस्त विजय दिलाई तो क्यों! पहला सबसे बड़ा कारण हिन्दू मुस्लिम का ध्रुवीकरण रहा है। दूसरा लोगों ने 2007 में मुलायम सिंह की गुंडाराज से परेशान होकर एकतरफा वोटिंग बीएसपी के पक्ष में किया या जिसे सोशल इंजि. नियरिंग दलित एवं ब्राह्मण एकजुटता कहा गया लेकिन यह गुण्डा राज को समाप्त करने के लिए था। ''उस समय का नारा होता था जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुण्डा।'' बहन जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पाषाण काल का अभ्युदय हुआ और फर्जी मुकदमों की बाढ़ आ गई और भ्रष्टाचार बढ़ता चला गया, इसके बाद 2012 के चुनाव में फिर सपा की कमान नए नवेले अखिलेश के हाथों में आई लोग बहन जी से दुःखी थे और अखिलेश ने डीपी यादव को टिकट न दे कर लोगों में भरोसा दिलाया कि वह स्वच्छ एवं गुण्डामुक्त सरकार दे सकते हैं, युवा हैं लोगों ने अप्रत्याशित बहुमत दिया लेकिन सत्ता में आते ही उनकी पार्टी पुनः मुलायम सिंह के शासन की तरह काम करने लगी। चारो ओर गुण्डा शासन, यादव राज स्थापित हो गया जनता त्राहि–त्राहि करने लगी कोई सुनने वाला ही नहीं पत्रकार को जिंदा जला दिया गया, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को न्यायालय ने हटाया, मथुरा में इतनी बड़ी घटना हुई कि एक पुलिस अधिकारी तक की मौत हो गई। इस तरह से लोग सपा, बसपा से पूरी तरह से भयभीत थे। वह पहले तो किसी राष्ट्रीय पार्टी की सरकार चाहते थे, जिसमें दो ही पार्टी थी, कांग्रेस व भाजपा। कांग्रेस पार्टी ने भी 27 साल यूपी बेहाल का नारा देकर प्रचार किया और अपने पक्ष में वोट मांगे। लेकिन बाद में सपा से गठबंधन कर लिया। इसके बाद जनता एवं कांग्रेस के कुछ लोगों के पास एक ही रास्ता था भाजपा और उसमें खाद और पानी का काम किया मोदी जी के लच्छेदार भाषण ने। जहां तक विकास की बात है वह तो दूर की कौड़ी है जब सांसद एक गांव का विकास नहीं कर सकते तो प्रदेश का विकास एक स्वप्न जैसा है। लोग वही फिल्म देखना चाहते हैं जिस फिल्म को हीरो अपने अभिनय कला से लोगों को प्रभावित कर अच्छे डॉयलॉग बोले, अच्छी फाइट करे, और लोगों का मनोरंजन करे। लोकतंत्र के इस तथाकथित हीरो का या यूं कहें पूरी फिल्म वास्तविकता से कोसो दूर है। हां योगी जी की शुरुआत धुआंधार ओपनिंग के साथ हुई है जो उत्तर प्रदेश जैसे बीमारु राज्य के लिए एक अच्छा संकेत है। अब प्रदेश में लग रहा है कि बरसो बाद कोई दमदार व्यक्ति प्रदेश का मुखिया बना है। जिसके हाथ में शासन प्रशासन की नकेल है। लोगों को योगी जी से उम्मीदें जगी हैं और एक सकारात्मक माहौल बन रहा है।

जो कार्य हाथ में लो, वह निश्चय से करो तो सफलता अवश्य होगी।

मोदी का यूपी फतह

मुजफ्फरनगर में सभी सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। बुढ़ाना सीट पर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को हराया। चारथावल सीट पर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को हराया। खतौली सीट पर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को हराया। मुजफ्फरनगर सीट पर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को हराया। मीरापुर सीट पर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को हराया। पुरकाजी सीट पर बीजेपी ने कांग्रेस के उम्मीदवार को हराया। खास बात ये कि एक सीट को छोड़कर सभी सीटों पर सपा के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे।

वाराणसी पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है। पूर्वांचल पर फतह पाने के लिए बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व और खुद पीएम मोदी ने वाराणसी में जमावड़ा रखा। वाराणसी से पूर्वांचल की फतह का फलसफा बीजेपी के काम भी आया। वाराणसी की आठ में से 6 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। जबकि बाकी दो सीटों पर उनके सहयोगी दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और अपना दल ने जीत दर्ज की। अजगरा सीट सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने जीत दर्ज की और सेवापुरी पर अपना दल ने समाजवादी को हराया। वहीं पिंडरा सीट बीजेपी ने बीएसपी को हराया। जबकि रोहनिया, शिवपुर सीट पर बीजेपी ने सपा को हराया। इसके अलावा वाराणसी छावनी, वाराणसी उत्तर और वाराणसी दक्षिण सीट पर बीजेपी ने कांग्रेस के उम्मीदवारों को मात दी।

पीएम मोदी ने वाराणसी के जनाधार का सम्मान किया। मोदी ने ट्वीट कर वाराणसी की जनता को धन्यवाद दिया। वहीं नोएडा में भी बीजेपी का परचम लहराया। नोएडा सीट की बात की जाए तो गृहमंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह ने समाजवादी पार्टी के सुनील चौधरी को हराया। हालांकि टिकट बंटवारे के वक्त काफी खींचतान देखने को मिली। लेकिन आखिरकार पंकज ने बंपर जीत के साथ अपने राजनीतिक कद को साबित किया। दादरी का मुद्दा देशभर में छाया रहा। बीफ के शक में अखलाक की हत्या कर दी गई। बीजेपी ने जहां इसे गोसेवा से जोड़ा। वहीं सपा ने भी इस मसले पर जमकर राजनीति की। अखलाक की हत्या के आरोप में कई लोग जेल गए। बीजेपी ने सपा सरकार पर बेकसूर नौजवानों को फंसाने का आरोप लगाया। चुनाव नतीजे बीजेपी के पक्ष में रहे। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार तेजपाल सिंह नागर ने जीत दर्ज की। तेजपाल ने बीएसपी उम्मीदवार सतवीर सिंह गुर्जर को 80 हजार से ज्यादा वोटों से हराया।

यही नहीं मोदी लहर में अमेठी–रायबरेली से उखड़ गईं कांग्रेस की जड़ें

अमेठी और रायबरेली जिसे हम कांग्रेस का गढ़ मानते रहे हैं बीजेपी की लहर में बह गया। अमेठी और रायबरेली दोनों जिलों में 10 विधानसभाएं हैं जिनमें बीजेपी और सपा–कांग्रेस गठबंधन के बीच सीधी टक्कर थी।

पांच सीटों पर बीजेपी जीत चुकी है और 5 सीटों पर सपा–कांग्रेस का गठबंधन। कांग्रेस के लिए नाक का सवाल बनी अमेठी सीट पर बीजेपी की गरिमा सिंह जीत गईं। वहीं रायबरेली से कांग्रेस उम्मीदवार अदिति सिंह ने जीत दर्ज की है। हालांकि अदिति सिंह की जीत में किसी पार्टी का काम उनके पिता अखिलेश सिंह का दमखम ज्यादा नजर आता है। आपको याद दिला दें कि पिछले विधानसभा चुनावों में रायबरेली जिलों की सभी पांच सीटें कांग्रेस हार गई थी. इन चुनावों में भी कांग्रेस के हाथ सिर्फ दो सीटें हैं। क्या इसका मायने यह नहीं निकालना चाहिए कि कांग्रेस लगातार अपना गढ़ हारती जा रही है। इस बार भी रायबरेली में एक सीट अखिलेश सिंह के परिवार से आई है तो दूसरी सीट (हरचंदपुर) पर सपा गठबंधन का फायदा नजर आया है क्योंकि पिछले चुनावों में इस सीट से सपा का विधायक था। आपको याद दिला दें कि रायबरेली की सभी विधानसभाएं सोनिया गांधी की लोकसभा क्षेत्र में आती हैं। रायबरेली में बाकी दो सीटों पर बीजेपी जीती तो एक पर सपा ने अपना झंडा बुलंद किया. इसी तरह अमेठी भी कांग्रेस के हाथ से फिसल चुका है। राहुल की अमेठी में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली. राहुल गांधी के लोकसभा क्षेत्र की 5 विधानसभा सीटों में से 4 पर बीजेपी ने कब्जा जमाया जबकि एक सीट पर सपा ने। मतलब साफ है कि अमेठी पर कांग्रेस की पकड़ कमजोर नहीं हुई बल्कि छूट चुकी है।

योगी ने 21 साल की उम्र में छोड़ दिया था घर

उत्तर प्रदेश में योगी राज की शुरुआत हो गई है। योगी आदित्यनाथ की देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री के तौर पर ताजपोशी हो गई। सीएम बनने पर उनके पूरे गांव और परिवार में खुशी का माहौल है। आदित्यनाथ ने 21 साल की उम्र में ही परिवार छोड़ दिया था और वो गोरखपुर आ गए थे। उनके पिता 24 साल पहले उत्तराखंड के एक गांव से संन्यास की दीक्षा लेने वाले बेटे को मनाने आए थे, लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा. मां मायूस हो गई, लेकिन बेटे के लिए लगातार दुआएं मांगती रही। वो संन्यासी बेटे के सीएम बन जाने से पूरा गांव जश्न मना रहा है।

योगी आदित्यनाथ का असली नाम अजय सिंह बिष्ट है। योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के एक छोटे से गांव पंचूर में हुआ, उनके पिता का नाम आनंद सिंह बिष्ट हैं जो गांव में रहते हैं। योगी आदित्यनाथ के भाई महेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि आदित्यनाथ में बचपन से सेवा भावना थी। हालांकि, उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वे सीएम पद तक पहुंचेंगे। महेंद्र सिंह ने कहा कि वह हमेशा से ही समाजसेवा की भावना थी और उसी दिशा में आगे बढ़े। उनके भाई बोले कि योगी 1993 में गोरखपुर चले गए।

संन्यास लेने के बाद बेटे का नाम बदल गया और ठिकाना भी बदल गया। उत्तराखंड के पंचुर गांव का अजय सिंह बिष्ट आज सत्ता के शीर्ष पर पहुंच चुके हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं खुशी इतनी है कि मां संन्यासी बेटे की तस्वीर को गोद में लिए बैठी है और उसकी कामयाबी की खुशी पिता की आंखो में छलक रही है। योगी के बड़े भाई बड़े गौरव से भाई अजय के बारे में बात करते हैं, उनके बारे में बताते हैं. योगी के पिता आनंद सिंह बिष्ट का कहना है कि यूपी में गुंडाराज खत्म होना चाहिए और सबका साथ सबका विकास होना चाहिए. उम्मीद ये भी है कि उनके गांव में मौजूद बाबा गोरखनाथ डिग्री कॉलेज का अब उद्धार हो जाएगा और वो अब सरकारी कॉलेज बन जाएगा। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के रहने वाले योगी चार भाई और तीन बहनों में दूसरे नंबर के भाई हैं। उनके दो भाई कॉलेज में नौकरी करते हैं, जबकि एक भाई सेना की गढ़वाल रेजिमेंट में सूबेदार हैं। योगी आदित्यनाथ पौड़ी गढ़वाल के इस गांव से संन्यास और राजनीति का लंबा सफर तय कर चुके हैं।

एजेंसी

यूपी के 21वें सीएम बने योगी

योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। कांशीराम स्मृति उपवन में हुए समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण आडवाणी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे. समारोह में 9 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पूर्व सीएम अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव मौजूद रहे।

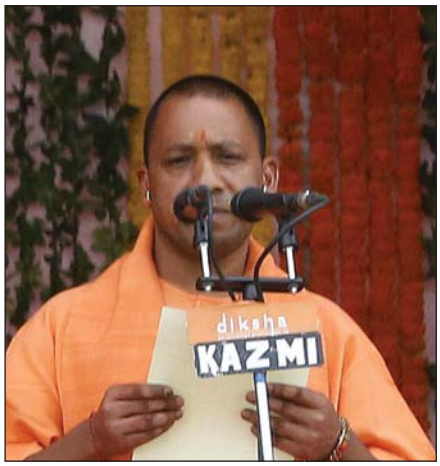

योगी आदित्यनाथ के साथ दो उप–मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा समेत 22 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली है. इनमें श्रीकांत शर्मा, सतीश महाना, राजेश अग्रवाल, लक्ष्मीनारायण चौधरी, सुरेश खन्ना, सत्यदेव पचौरी, जयप्रताप सिंह, ओमप्रकाश राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य, जयप्रकाश सिंह, सिद्धार्थनाथ सिंह, नंदगोपाल नंदी, दारा सिंह चौहान, एसपी सिंह बघेल, धरमपाल सिंह, रमापति शास्त्री, बृजेश पाठक, राजेंद्र सिंह, मुकुल बिहारी, आशुतोष टंडन और रीता बहुगुणा शामिल हैं.

उन्होंने गढ़वाल विश्वविद्यालय से गणित में बीएससी किया है। वो गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के महंत हैं। आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर के पूर्व महंत अवैद्यनाथ के उत्तराधिकारी हैं। वो हिंदू युवा वाहिनी के संस्थापक भी हैं, जो कि हिन्दू युवाओं का सामा. जिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी समूह है।

कट्टर हिंदुत्व की छवि : कट्टर हिंदुत्व की राह पर चलते हुए उन्होंने कई बार विवादित बयान दिए। योगी विवादों में बने रहे, लेकिन उनकी ताकत लगातार बढ़ती गई. 2007 में गोरखपुर में दंगे हुए तो योगी आदित्यनाथ को मुख्य आरोपी बनाया गया, गिरफ्तारी हुई और इस पर कोहराम भी मचा. योगी के खिलाफ कई अपराधिक मुकदमे भी दर्ज हुए. बता दें कि उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में से बीजेपी को 312, सपा को 47, कांग्रेस को 7, राष्ट्रीय लोक दल को 1, बसपा 19, अपना दल को 9, एनआईएसएचएडी को 1, सुखदेव भारतीय समाज पार्टी को 4 और अन्य के खाते में 3 सीटें गई हैं।

एजेंसी

ईश्वर का स्मरण करने से हमारी शान्ति व खुशी का खाता बढ़ जाता है।

योगी के मंत्रियों को क्या मिला

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सरकार के शपथ ग्रहण के बाद मंत्रालय का बंटवारा किया गया। इससे पहले गोरखपुर से लोकसभा सांसद योगी आदित्यनाथ को यूपी का मुख्यमंत्री बनाया गया। उनके साथ केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा को यूपी का उपमुख्यमंत्री बनाया गया। नई सरकार में दो डिप्टी सीएम के साथ 46 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। इनमें 22 कैबिनेट मंत्री, 9 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), 13 राज्यमंत्री हैं। मंत्रियों के विभाग की सूची राज्यपाल भवन भेज दी गई है।

आदित्यनाथ के पास ये मंत्रालय योगी आदित्यनाथ ने गृह मंत्रालय के अलावा आवास एवं शहरी नियोजन, राजस्व, खाद्य एवं रसद, नागरिक आपूर्ति, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, कारागार, सामान्य प्रशासन, सचिवालय प्रशासन, सर्तकता, नियुक्ति, कार्मिक, सूचना, निर्वाचन, संस्थागत वित्त, नियोजन, राज्य सम्पत्ति, नगर भूमि, आदि विभाग भी अपने पास रखे हैं।

कैबिनेट मंत्री उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या को लोक निर्माण विभाग, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा संसदीय कार्य मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री, सूर्य प्रताप शाही को कृषि, कृषि शिक्षा, कृषि अनुसंधान, सुरेश खन्ना को संसदीय कार्य, नगर विकास, शहरी समग्र विकास, स्वामी प्रसाद मौर्य को श्रम एवं सेवा योजना, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन,सतीश महाना को औद्योगिक विकास, राजेश अग्रवाल को वित्त, रीता बहुगुणा जोशी को महिला कल्याण, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण, पर्यटन, दारा सिंह चौहान को वन एवं पर्यावरण, जन्तु उद्यान, उद्यान दिया गया है।

नंदी को स्टाम्प धरमपाल सिंह को सिंचाई, सिंचाई (यांत्रिक), एसपी सिंह बघेल को पशुधन, लघु सिंचाई, मत्स्य, सत्यदेव पचौरी को खादी, ग्रामोद्योग, रेशम, वस्त्रोद्योग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, निर्यात प्रोत्साहन, रमापति शास्त्री समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, जय प्रकाश सिंह को आबकारी, मद्यनिषेध,ओम प्रकाश राजभर को पिछड़ा वर्ग कल्याण, विकलांग जन विकास, बृजेश पाठक को विधि एवं न्याय, अतिरिक्त उर्जा स्रोत, राजनैतिक पेंशन, लक्ष्मी नारायण चौधरी को दुग्ध विकास, धमार्थ कार्य, संस्कृति, अल्पसंख्यक कल्याण, चेतन चौहान को खेल एवं युवा कल्याण, व्यवसायिक शिक्षा, कौशल विकास, श्रीकांत शर्मा को ऊर्जा, राजेन्द्र प्रताप सिंह को ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, सिद्धार्थ नाथ सिंह को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, मुकुट बिहारी वर्मा को सहकारिता, आशुतोष टण्डन को प्राविधिक शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा, नंद कुमार नंदी को स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क, पंजीयन नागरिक उड्डयन विभाग मिला है।

योगी राज में राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) को मिला ये अनुपमा जैसवाल को बेसिक शिक्षा, बाल विकास एवं पुष्टाहार, राजस्व (एमओएस), वित्त (एमओएस) , सुरेश राणा को गन्ना विकास एवं चीनी मिलें, औद्योगिक विकास (एमओएस), उपेन्द्र तिवारी को जल सम्पूर्ति, भूमि विकास एवं जल संसाधन, परती भूमि विकास, वन एवं पर्यावरण, जन्तु उद्यान, उद्यान, सहकारिता (एमओएस), डॉ. महेन्द्र सिंह को ग्रामीण विकास, समग्र ग्राम विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (एमओएस), स्वतंत्रदेव सिंह को परिवहन, प्रोटोकॉल, ऊर्जा (एमओएस), भूपेन्द्र सिंह चौधरी को पंचायती राज, लोक निर्माण (एमओएस), धर्म सिंह सैनी को आयुष, अभाव सहायता एवं पुनर्वास, अनिल राजभर को सैनिक कल्याण, खाद्य प्रसंस्करण, होमगार्डस, प्रांतीय रक्षक दल, नागरिक सुरक्षा, स्वाति सिंह को एनआरआई, बाढ़ नियंत्रण कृषि निर्यात, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार, महिला कल्याण, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण विभाग (एमओएस) मिला है।

गुलाबो देवी को समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजा. ति कल्याण , जय प्रकाश निषाद को पशुधन एवं मत्स्य, राज्य सम्पत्ति, नगर भूमि, अर्चना पांडेय को खनन, आबकारी, मद्यनिषेध, जय कुमार सिंह जैकी को कारागार, लोक सेवा प्रबंधन, अतुल गर्ग को खाद्य रसद, नागरिक आपूर्ति, किराया नियंत्रण, उपभोक्ता संरक्षण, बाट माप, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, रणवेन्द्र प्रताप सिंह को कृषि, कृषि शिक्षा, कृषि , नीलकंठ तिवारी को विधि न्याय, सूचना, खेल एवं युवा कल्याण. मोहसिन रजा को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी, मुस्लिम वक्फ, हज, गिरीश यादव को नगर विकास, अभाव सहायता एवं पुनर्वास, बलदेव ओलाख को अल्पसंख्यक कल्याण, सिंचाई, सिंचाई (यांत्रिक), मन्नु कोरी को श्रम सेवा योजना, संदीप सिंह को बेसिक, माध्यमिक, उच्च, प्राविधिक, चिकित्सा शिक्षा, सुरेश पासी को आवास, व्यवसायिक शिक्षा, कौशल विभाग मिला है।

170 घंटों में 50 फैसले

लखनऊ। 170 घंटों में 50 फैसले कर योगी आदित्य नाथ ने जाहिर की मंशा, पिछले 40 साल में सचिवालय का दौरा करने वाले पहले सीएम योगी ने अपने इस दौरे के दौरान सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों तथा विद्यालयों में पान, तम्बाकू तथा पान मसाला खाने पर पाबंदी लगा दी और सभी अधिकारियों को स्वच्छता रखने की शपथ दिलायी।

उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के महज एक सप्ताह के अंदर समूचे मंत्रिमण्डल और नौकरशाही को अनुशासन तथा ईमानदारी को लेकर अपने 'हठयोग' का सुस्पष्ट संदेश देने वाले आदित्यनाथ योगी ने इस छोटी सी अवधि में करीब 50 नीतिगत फैसले लेकर अपने इरादे जाहिर कर दिये हैं। मुख्यमंत्री ने पदभार ग्रहण करने के अगले ही दिन सचिवालय का औचक निरीक्षण करके यह जाहिर कर दिया कि वह सरकारी तंत्र में वक्त की पाबंदी, काम में ईमानदारी और कार्यालय में स्वच्छता के मामले में कोई समझौता नहीं करेंगे। पिछले 40 साल के दौरान सचिवालय का दौरा करने वाले वह पहले मुख्यमंत्री हैं।

योगी ने अपने इस दौरे के दौरान सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों तथा विद्यालयों में पान, तम्बाकू तथा पान मसाला खाने पर पाबंदी लगा दी और सभी अधिकारियों को स्वच्छता रखने की शपथ दिलायी। उसके अगले ही दिन उनकी सरकार के एक मंत्री अपने कार्यालय में झाड़ू लगाते और कई मंत्री फाइलों में जमी धूल साफ करते नजर आये। गोरक्षा

न किसी के धोखे में आओ, न किसी को धोखे में डालो।

पीठाधीश्वर मुख्यमंत्री योगी ने गोरखपुर के अपने दौरे के दौरान अपनी टीम को कर्तव्यनिष्ठा का संदेश देते हुए कहा कि जो लोग 18–20 घंटे काम करना चाहते हैं, वे ही उनके साथ रहें, बाकी लोग अपना रास्ता खुद तय कर लें।

उन्होंने कहा कि वह दो महीने में ऐसा माहौल तैयार करेंगे जिससे लोगों को बदलाव महसूस होगा और उन्हें यह पता चलेगा कि सरकार कैसे चलायी जाती है। योगी ने अपनी कैबिनेट की पहली बैठक का इंतजार किये बगैर तेजतर्रार ढंग से काम शुरू किया। अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई और एंटी रोमियो दलों के जरिये शोहदों पर शिकंजा कसा जाना इसका उदाहरण है। उन्होंने कानून–व्यवस्था को अपनी पहली वरीयता के तौर पर लेते हुए अपराधियों को चेतावनी दी कि वे उत्तर प्रदेश छोड़कर चले जाएं। मुख्यमंत्री ने भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं से साफ कहा कि वे सरकारी ठेके ना लें, बल्कि विकास कार्यों की निगरानी करें।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का 'ड्रीम प्रोजेक्ट' रहे 'गोमती रिवरफ्रण्ट विकास परियोजना' का निरीक्षण किया और उसकी प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया। योगी ने करीब 1500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली गोमती रिवरफ्रण्ट परियोजना का निरीक्षण करते हुए कहा कि मई 2017 तक पूरी हो जाने वाली इस परियोजना का अभी तक 60 फीसदी से भी कम काम हो पाया है।

इस पर अब तक 1427 करोड़ रुपये खर्च हो चुकने के बावजूद विभाग द्वारा लगभग 1500 करोड़ रुपये अतिरिक्त उपलब्ध कराने की मांग की जा रही है। योगी ने इस बात पर नाराजगी व्यक्त की कि लगभग 1400 करोड़ रुपये से अधिक व्यय करने के बाद भी गोमती नदी में गिरने वाले नालों को रोका नहीं जा सका है। कार्यदायी संस्थाओं ने फव्वारे जैसे गैर–जरूरी कामों पर जनता की गाढ़ी कमाई को खर्च कर दिया और लखनऊ की जनता को इसका कोई लाभ भी नहीं मिल पा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने सुझाया बातचीत का रास्ता, क्या आपसी सहमति से सुलझ पाएगा अयोध्या विवाद?

अयोध्या में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो विवाद 1949 से कानूनी पेंच में उलझा हुआ है, अब सुप्रीम कोर्ट ने उसे आपसी बातचीत से सुलझाने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या विवाद का जल्द निपटारा कराने के लिए बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका दाखिल की थी कि इस मुकदमे की सुनवाई रोजाना की जाए। सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस जे एस खेहर की बेंच ने कहा कि मामला आस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए बेहतर होगा कि मुकदमे से जुड़े सभी पक्ष आपस में मिल–बैठकर बात. चीत से सुलझाने की कोशिश करें। अब सवाल ये उठते हैं कि क्या आपसी सहमति से सुलझेगा अयोध्या विवाद? सुप्रीम कोर्ट को क्यों लगा कि मंदिर और मस्जिद के कानूनी विवाद से जुड़े सभी पक्षों के मिल–बैठ कर बात करने से रास्ता निकल सकता है?

दूसरों की गलती सहन करना एक बात है, परन्तु उन्हें माफ कर देना और महान बात है।

जन्म–मृत्यु माया के मायाजाल

मृत्यु का अर्थ है भौतिक शरीर से आत्मा का जुदा होना। मृत्यु नये और बेहतर जीवन का एक प्रारंभिक बिन्दु बन जाता है। यह जीवन के उच्च रूप का द्वार खोलता है। यह संपूर्ण जीवन का केवल एक प्रवेशद्वार है। जन्म और मृत्यु माया के मायाजाल हैं। जन्म लेते ही मरने की शुरुआत हो जाती है और मरते ही जीवन की शुरुआत हो जाती है। जन्म और मृत्यु इस संसार के मंच पर प्रवेश करने और बाहर जाने का द्वार मात्र है वास्तव में ना तो कोई आता है और ना ही कोई जाता है। केवल ब्रह्म और अनंत का ही अस्तित्व होता है। जैसे आप घर से दूसरे घर में जाते हैं, वैसे ही आत्मा अनुभव प्राप्त करने के लिए एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनता है, बिलकुल वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। मृत्यु जीवन का अंत नहीं है। जीवन एक कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। यह निरंतर चलती ही रहती है। मृत्यु एक जरूरी घटना है जिसका अनुभव हर आत्मा को भविष्य में विकास करने के लिए करना है। एक विवेकी और बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी मौत से नहीं डरता है।

हर आत्मा एक चक्र है। इस चक्र की परिधि कहीं भी खत्म नहीं होती लेकिन इसका केन्द्र हमारा शरीर है। तो फिर, मौत से क्यों डरना चाहिए? परमात्मा या सर्वोच्च आत्मा मृत्युरहित, कालातीत, निराधार और असीम है। यह शरीर, मन और पूरे संसार के लिए एक केन्द्र है। मृत्यु केवल भौतिक शरीर को प्राप्त होती है, जो पांच तत्वों से बना है। मृत्यु शाश्वत आत्मा को कैसे मार सकती है जो समय, स्थान और कर्म से परे है? अगर आप जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको शरीर. विहीन होना होगा। शरीर हमारे कर्मों का परिणाम है। आपको कोई भी कार्य फल की उम्मीद किए बिना ही करना चाहिए। अगर आप खुद को रागद्वेष या पसंद और नापसंद से मुक्त कर लेते हैं, तो आप खुद को कर्म से भी मुक्त कर लेंगे। आप केवल अहंकार को ही खत्म कर खुद को 'राग' और 'द्वेष' से मुक्त कर सकते हैं। जब अविनाशी ज्ञान के द्वारा अज्ञानता का अंत हो सकता है तो आप अहंकार का भी विनाश कर सकते हैं। इसलिये इस शरीर के जड़ का कारण यह अज्ञानता है। जिसने भी उस अमर आत्मा का एहसास कर लिया जो सभी ध्वनि, दृश्य, स्वाद और स्पर्श से परे है, जो निराकार और निर्गुण है, जो प्रकृति से परे है, जो तीन शरीर और पांच तत्वों से परे है, जो अनंत और अपरिवर्तनीय है, उसने खुद को मौत के मुंह से आजाद कर लिया। जीव या व्यक्तिगत आत्मा अपने कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए और अनुभव प्राप्त करने के लिए अनेक शरीर धारण करती है। वो शरीर में प्रवेश करती है और फिर जब वह शरीर जीने लायक नहीं रहता, तो उसे त्याग देती है। वह फिर से एक नए शरीर का निर्माण करती और पुनः वही प्रक्रिया दोहराती है। यह प्रक्रिया स्थानांतरगमन कहलाती है। किसी नये शरीर में आत्मा का प्रवेश करना जन्म कहलाता है। शरीर से आत्मा का अलग हो जाना मृत्यु कहलाता है। अगर शरीर में आत्मा न हो तो वह शरीर मृत शरीर है और इसे प्राकृतिक मृत्यु कहते हैं। एक कोशकीय जीवों के लिए प्राकृतिक मृत्यु अज्ञात है। जब पृथ्वी पर ऐसे जीवों को जीवन मिलता है तो उनकी मृत्यु अज्ञात होती है। यह घटना केवल बहुकोशकीय जीवों के साथ ही होती है। प्रयोगशालाओं के शोधों से पता चला है कि किसी के जीवन की समाप्ति के बाद भी उसके अंग काम कर सकते हैं। मृत्यु के बाद भी कई महीनों तक सफेद रक्तकण शरीर में जीवित रहते हैं। मृत्यु जीवन का अंत नहीं है।

'जिंदा' पत्नी को पति ने श्मशान ले जाकर फूंक दिया

उत्तर प्रदेश की एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। उसमें पुलिस को शक है कि पति ने अपने परिवार के साथ मिलकर पत्नी को जिंदा जला दिया। हालांकि, यह बात अभी पुख्ता तौर पर साबित नहीं हुई है। यूपी पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। पुलिस को शक है कि 21 साल की एक लड़की को उसके पति ने जिंदा जला दिया था। लड़की को ग्रेटर नोएडा के शारदा हॉस्पिटल ने मृत घोषित किया था।

लेकिन अब दो डॉक्टरों के पैनल ने कहा कि उस लड़की की मौत जिंदा जलाए जाने के डर से लगे शॉक की वजह से हुई। शारदा हॉस्पिटल द्वारा जारी किए गए डेथ सर्टिफिकेट के हिसाब से लड़की की मौत रविवार रात को 11.45 पर हुई। उसके आठ घंटे बाद अलीगढ़ में उसका अंतिम संस्कार हो रहा था।

कैसे हुआ शक ? डॉक्टर्स ने कहा था कि लड़की की मौत फेफड़ों में हुए इनफेक्शन की वजह से हुई थी। वहीं जांच कर रहे पैनल के डॉक्टरों का कहना है कि लड़की के फेफड़ों और हवा की नली के अंदर जले कण मिले हैं और ऐसा तब ही होता है जब किसी को जिंदा जलाया जाता है। मर जाने के बाद वे कण शरीर में प्रवेश नहीं कर सकते। कैसे पहुंची पुलिस ? लड़की के भाई को अपनी बहन की मौत पर शक था। उसने अलीगढ़ पुलिस को सूचित किया था। जिस वक्त पुलिस ने पहुंचकर लाश को निकाला जबतक वह 70–80 प्रतिशत जल गई थी।

उसके बाद लड़की के अंकल ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। उन्होंने लड़की के पति समेत उसके परिवार के 10 लोगों पर लड़की से बलात्कार करके उसे मारने का आरोप लगाया है। फिलहाल सभी आरोपी फरार हैं। लड़की बुलंदशहर की रहने वाली थी उसकी दो साल पहले शादी हुई थी। जिसके बाद वह नोएडा रहने लगी थी।

सबसे बड़ी सेवा है जीवन की खुशियों को दूसरों के साथ बांटना।

तिरंगे को दिवालियापन मानता रहा है आरएसएस/संघ

राम प्रकाश त्रिपाठी

दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज में जारी विवाद में आरएसएस समर्थकों के हाथ में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का होना चौंकाता है। यूनिवर्सिटी स्तर पर इससे पहले भी राष्ट्रवाद को लेकर कई विवाद उभरे हैं, लेकिन आरएसएस विचारधारा के मुरीदों ने तिरंगा कभी नहीं थामा। सोशल मीडिया में इस तरह की कई तस्वीरें छा गईं, जो कई अहम सवाल उकेरती हैं।

संघ तिरंगा की अवधारणा को पूरी तरह से मानता ही नहीं। आरएसएस के दूसरे सर संघचालक एमएस गोलवलकर ने अपनी किताब 'विचार नवनीत' में तिरंगे के चयन पर सवाल उठाते हुए कहा है कि नया झंड़ा चुनना हमारी समृद्ध विरासत को अस्वीकृत करना है। उन्होंने साफ कहा है, 'क्या हमारे पास अपना एक झंडा तक नहीं है बेशक हमारे पास है, तो फिर यह दिवालियापन क्यों ऐसे में तिरंगे के साथ स्वयंसेवकों के दिखने से आए बदलाव के मायने क्या हैं क्या आरएसएस ने तिरंगे की संविधान प्रदत्त मान्यता को स्वीकार कर लिया है नहीं, ऐसा नहीं है।

संघ का मानना है कि तिरंगा देश का शासकीय और भगवा सांस्कृतिक ध्वज है। वैसे भी वर्ष 1950 में आरएसएस से प्रतिबंध हटने के बाद वर्ष 2002 तक दिखावे के लिए भी स्वयंसेवकों ने कभी तिरंगा नहीं फहराया। वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संघ मुख्यालय नागपुर में गणतंत्र दिवस पर तिरंगा जरूर फहरवाया था। इसके बावजूद संविधान और तिरंगे के प्रति संघ के नजरिए में कोई खास बदलाव नहीं देखा गया है।

तिरंगे के प्रति आरएसएस का रूख राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के बाद 4 फरवरी, 1948 को हिंसक रूप में उभरा था। इस पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 24 फरवरी को अपने एक भाषण में कहा था कि खबरें आ रही है कि आरएसएस के सदस्य तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। ऐसा करके वे अपने आप को देशद्रोही साबित कर रहे हैं। इसके बाद संघ पर प्रतिबंध लगा, जो कई कसमें खाकर दिखाने के बाद हटा। प्रतिबंध हटाने की एवज में तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने देश के संविधान और तिरंगे पर आस्था व विश्वास की शर्त रखी थी, जिसे सर संघचालक गोलवलकर ने लिखित रूप से स्वीकार किया था।

इसके बावजूद गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराने की कोई प्रथा संघ में शुरू नहीं हुई थी। यह दीगर बात है कि चीन युद्ध के बाद सन 1963 में देश के प्रधानमंत्री नेहरू के न्यौते पर संघ के स्वयंसेवक गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हुए थे। तिरंगा विरोध की इस लंबी श्रृंखला के बाद इस वर्ष 2017 में संघ पदाधिकारी प्रमुखता से गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहरवाते हुए दिखे हैं। वैसे वर्ष 2016 में भी ऐसे कुछ छिटपुट कार्यक्रम हुए थे, लेकिन इस बार बड़े पैमाने पर गांव व बस्तियों में सूचीबद्ध तरीके से इस प्रकार के आयोजन हैरत में डालते हैं। आखिर यह सब किस राजनीति का सूचक है।

संघ के दिल्ली प्रदेश प्रचारक व बौद्धिक प्रमुख सतीश शर्मा इस विषय पर बातचीत में कहते हैं, 'समय के साथ परिवर्तन जरूरी है। संघ देश–समाज के साथ है। इंदिरा जी हमसे निक्कर नहीं छुड़वा पाईं। उसे संघ ने अपनी मर्जी से छोड़ा और फुलपैंट अपनाई है। नेहरू ने प्रतिबंध लगाया और बाद में 26 जनवरी की परेड में बुलाया था। अगर हम (आरएसएस) गलत होते तो परेड में मार्च क्यों करते। हम जितना सम्मान भगवा ध्वज का करते हैं, उतना ही तिरंगे का भी।'

देशकाल में स्थिति बदलती है, लेकिन संघ के इस परिवर्तन के मायने क्या हैं बीजेपी के सत्ता में काबिज होने के बाद यह कदम वैचारिक है या राजनीतिक चूंकि आरएसएस खुद को वैचारिक संगठन और सत्ता की राजनीति को 'गंदा नाला' मानता रहा है।

इस कारण स्वयंसेवक राजनीति से दूर ही रहे हैं, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में आरएसएस खुलकर इस गंदे नाले में नहाया है। तय है कि जिस संविधान में उसकी राष्ट्रवादी मानसिकता के कारण आस्था नहीं, उसे भी परोक्ष रूप से थोड़ा–बहुत मानना जरूरी है। क्या इस परिवर्तन का अर्थ सत्ता पर काबिज रहने का प्रयास है या कुछ और क्योंकि धर्मनिरपेक्ष गणतांत्रिक व्यवस्था में किसी एक धर्म या मजहब का शासन नहीं है और अगर ऐसा होगा तो गणतंत्र नहीं होगा।

शशिकला से पहले 5 और नेताओं की महत्वाकांक्षाओं पर चला कोर्ट का डंडा

आय से अधिक संपत्ति के मामले में सजा पाने के बाद अन्नाद्रमुक (AIADMK) की महासचिव वीके शशिकला की राजनीतिक महत्वाकांक्षा पर ब्रेक लग गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के चलते शशिकला 10 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। अब वह किसी पार्टी की सदस्य तो रह सकती हैं, लेकिन सरकार का हिस्सा नहीं बन पाएंगी। शशिकला देश की पहली ऐसी बड़ी नेता नहीं हैं जिन्हें सजा की वजह से कुर्सी का मोह छोड़ना पड़ा है। आइए जानें देश में वे कौन–कौन बड़े नेता हैं जो सजायाफ्ता होने के चलते चुनाव नहीं लड़ पाते हैं।

1– रशीद मसूद : सजा के चलते चुनाव लड़ने का अधिकार गंवाने वाले नेताओं में सबसे पहला नाम कांग्रेस के रशीद मसूद को जाता है। दिल्ली की एक अदालत ने 1990–91 में अयोग्य छात्रों को फर्जी तरीके से एमबीबीएस सीट दिलाने के मामले में मसूद को दोषी ठहराया था और चार साल की सजा सुनाई थी। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने मसूद (67) को भ्रष्टाचार और अन्य मामलों में दोषी करार दिया था। उन्हें त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज को केंद्रीय कोटे से आवंटित सीटों पर अयोग्य छात्रों को फर्जी तरीके से नामित करने के मामले में दोषी पाया गया था। उत्तर प्रदेश में रशीद मसूद कांग्रेस के बड़े नेता थे। वे विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार में 1990 से 1991 तक स्वास्थ्य मंत्री रहे।

2–लालू प्रसाद यादव : चारा घोटाले में पांच साल की सजा पा चुके बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। हालांकि लालू अभी भी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पर्दे के पीछे से मुख्यधारा की राजनीति में सक्रिय हैं। इस समय बिहार में उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के पास सबसे ज्यादा सीटें हैं और उनके बेटे तेजस्वी यादव राज्य के उपमुख्यमंत्री हैं। लालू यादव को विशेष सीबीआई अदालत ने चारा घोटाले के चाईबासा कोषागार से फर्जी ढंग से 37.7करोड़ रुपये निकालने के मामले में पांच वर्ष के कठोर कारावास और 25 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। फिलहाल लालू सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में जमानत पर हैं।

3–जगन्नाथ मिश्र : बिहार के ही पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र सजायाफ्ता होने के चलते चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। उन्हें भी चारा घोटाले में चार वर्ष कैद और दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। फिलहाल जगन्नाथ मिश्र भी जमानत पर हैं।

4– ओम प्रकाश चौटाला : शिक्षक भर्ती घोटाले में 10 साल की सजा पा चुके हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला का राजनीतिक सफर थम गया है। उनके बेटे अजय चौटाला भी उनके साथ सजायाफ्ता हैं। दोनों पिता–पुत्र चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। चार बार मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला और उनके विधायक बेटे अजय चौटाला को दिल्ली की रोहणी कोर्ट ने 10–10 साल की सजा सुनाई है। 1999–2000 में चौटाला के मुख्यमंत्री रहते हुए 3206 जूनियर बेसिक टीचरों की भर्ती हुई थी। इस समय हरियाणा में आईएनएलडी की सरकार थी और ओम प्रकाश चोटाला राज्य के मुख्यमंत्री थे। अब ओपी चौटाला के पोते दुष्यंत चौटाला उनकी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का संचालन कर रहे हैं।

5–जगदीश शर्मा : बिहार के जदयू सांसद जगदीश शर्मा भी कोर्ट से दो साल से ज्यादा सजा पाने के चलते चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। इन्हें सांसद रहते हुए सजा हुई थी। जगदीश शर्मा को विशेष सीबीआई अदालत ने चारा घोटाले के गोड्डा कोषागार से अवैध निकासी के एक मामले में चार साल के सश्रम कारावास और चार लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी थी। मालूम हो मुख्यमंत्री रह चुके झारखंड के शिबू सोरेन और मधु कोड़ा भी जेल में रहे हैं, लेकिन उनपर अबतक केवल आरोप रहा है, इसलिए वे अभी तक चुनाव लड़ पा रहे हैं।

यदि आप केवल अपना ही ध्यान रखेंगे तो दूसरे आपका ध्यान रखना कम कर देंगे।

पुलिस की ओर से मीडिया को जानकारी देने के बारे में गाइडलाइन तय करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट पुलिस द्वारा मीडिया में दी जाने वाली अपराध की खबरों पर गाइडलाइन जारी करेगा। गिरफ्तारी के बाद किसी आरोपी की मीडिया परेड होगी या नहीं, यह सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। आरोपी और पीड़ित की पहचान को लेकर भी गाइडलाइन जारी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट यह भी तय करेगा कि पुलिस आपराधिक मामलों में मीडिया को किस तरीके से और कितनी जानकारी जारी करे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कुछ सवालों के केंद्र सरकार और सब राज्य सरकारों से दो हफ्ते में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो कोई जवाब दाखिल नहीं करेगा तो यह समझा जाएगा कि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। चीफ जस्टिस खेहर ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा पुलिस किसी केस में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है और बिना जांच किए ही आरोपी को प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने पेश करती है। यदि आरोपी बाद में निर्दोष पाया जाता है तो भी उसकी साख खराब हो चुकी होती है। यह एक गंभीर मामला है क्योंकि यह सीधे–सीधे हर नागरिक की प्रतिष्ठा से जुड़ा है। 1999 से यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में है और अब तक सारा मामला हवा में है। लेकिन हम इस गंभीर मसले को लटकाना नहीं चाहते और जल्द ही इस पर फैसला देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कई सवालों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से जवाब मांगा है और उनके सुझाव मांगे हैं। पूछा गया है कि एफआईआर दर्ज होने से पहले मीडिया को आरोपी और अपराध के बारे में कितनी जानकारी दी जाए? एफआईआर दर्ज होने के बाद मीडिया को आरोपी के बारे में किस हद तक जानकारी दी जा सकती है? आरोपी के गिरफ्तार होने पर क्या उसकी फोटो या वीडियो दिया जा सकता है? क्या मीडिया के सामने परेड कराई जा सकती है? पीड़ित की पहचान संबंधी ब्यौरा दिया जा सकता है? किसी मामले की जांच से जुड़े ब्योरे को मीडिया के साथ साझा किया जा सकता है? किस हद तक? ऐसा मामला जिससे सामुदायिक हिंसा भड़कने की आशंका हो तो मीडिया को घटना के बारे में किस हद तक ब्यौरा दिया जाए? ऐसी सूचना जिससे अपराध करने वाला पुलिस से बचने के लिए सतर्क हो जाए, कैसे मीडिया को दी जाए? महिलाओं के साथ होने वाले यौन संबंधी अपराधों में पीड़िता और उसकी किसी भी तरह की पहचान वाला ब्यौरा मीडिया को दिया जाए? ऐसे मामले जिनमें नाबालिग शामिल हो, उनमें क्या किया जाए? क्या हर थाने में पुलिस प्रवक्ता नियुक्त किया जाए या फिर किस स्तर का पुलिस अफसर मीडिया को ब्रीफ करे?

लोकपाल की नियुक्ति मामला अब सुप्रीम कोर्ट में

लोकपाल की नियुक्ति के संबंध में केंद्र सरकार की तरफ से बताया गया कि लोकपाल बिल में कुछ संशोधन होने है, जो संसद में लंबित है। ऐसे में मामले की सुनवाई 4 हफ्ते के लिए टाल दी जाये। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि वह लोकपाल की नियुक्ति को लेकर पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करे। कोर्ट जानना चाहता है कि आखिर वे कौन से संशोधन हैं, जो लोकपाल बिल में किए जाने हैं। लोकपाल की नियुक्ति में हो रही देरी को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर यह समस्या दूर नहीं हो पा रही है तो कोर्ट आदेश दे सकता है कि एक्ट में LOP का मतलब संसद में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का नेता ही नेता विपक्ष होगा, वहीं अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहातगी ने कहा कि इस मामले में और भी कई मुद्दे हैं, जिन पर विचार किया जा रहा है। गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किया था कि लोकपाल एक्ट 2014 में बना था, तो अब तक यह प्रक्रिया पूरी क्यों नहीं हुई, और लोकपाल की नियुक्ति क्यों नहीं हो पाई है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोर्ट लोकपाल की नियुक्ति में इस तरह देरी होते नहीं देख सकता। लोकपाल को एक डेड लेटर नहीं बनने दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि सरकार ईमानदारी लाने के लिए अपनी रुचि दिखाते हुए लग रही है, लेकिन लोकपाल बिल में संशोधन क्यों नहीं ला रही है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केंद्र सरकार को इसके लिए कोई डेडलाइन तय करनी होगी और अगर यह काम केंद्र नहीं करता, तो सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सबसे बड़ी पार्टी के नेता को नेता विपक्ष होने का आदेश जारी कर देगा। वहीं इस मामले में केंद्र सरकार ने कहा है कि लोकपाल एक्ट में संशोधन करना है, और इसके लिए बिल संसद में लंबित है। एक्ट के मुताबिक सर्च कमेटी में नेता विपक्ष को होना चाहिए, लेकिन अभी कोई नेता विपक्ष नहीं है, इसलिए सबसे बड़ी पार्टी के नेता को कमेटी में शामिल करने के लिए एक्ट में संशोधन करना होगा, और यह संसद में लंबित है।

रिस्पेक्ट मांगने से नहीं, धारणा करने से मिलता है।

बिहार में कैदियों की भी मौज?

सुप्रीम कोर्ट कराएगा जेलों का CAG ऑडिट

2015–16 के आंकड़ों की मानें तो बिहार की जेलों में बंद कैदियों का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है। बिहार सरकार एक कैदी पर साल में औसतन 83,691 रुपये खर्च करती है, जबकि राजस्थान सरकार सिर्फ तीन हजार रुपये सालाना खर्च करती है। पंजाब में ये आंकड़ा 16,669 रुपये है, जबकि नगालैंड में 65,468 रुपये सालाना प्रति कैदी। ये आंकड़े किसी को भी चौंकाने के लिए काफी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इन पर अचरज जताया है। विभिन्न राज्यों में इस मद में अलग–अलग खर्च से हैरान सुप्रीम कोर्ट अब तमाम जेलों का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) से ऑडिट कराने की तैयारी कर रहा है। कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से 31 मार्च तक योजना मांगी है कि किस तरीके से जेलों के खर्च का ऑडिट कर पता लगाया जा सकता है कि ये पैसा सूझबूझ से खर्च किया जा रहा है या नहीं और कैदियों को इसका लाभ मिल भी रहा है या नहीं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में स्टाफ पर कमी पर भी चिंता जताते हुए केंद्र सरकार और सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 31 मार्च तक जेलकर्मियों की भर्ती के कदम उठाने को कहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एमिक्स क्यूरी ने 2014 को लोकसभा में रखे गए जवाब का हवाला दिया जिसमें बताया गया था कि 31 दिसंबर 2014 तक देश में 79,988 जेलकर्मियों के पद स्वीकृत थे, जबकि कुल 52,666 जेलकर्मी ही काम कर रहे हैं। यानी जेलों में 27 हजार कर्मियों के पद खाली हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जेलकर्मियों की ट्रेनिंग पर भी बड़े सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 50 हजार से ज्यादा जेल कर्मियों में से सिर्फ 7800 को ही किसी तरह की ट्रेनिंग दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि वो 31 मार्च तक राज्य सरकारों से बात कर जेलकर्मियों के लिए ट्रेनिंग का कोई मैन्युअल तैयार करे। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ किया है कि राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों को इस मामले मे केंद्र का सहयोग करना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भारी जुर्माना लगाया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई 12 अप्रैल को करेगा। दरअसल, 2013 में पूर्व मुख्य न्यायाधीश आरसी लाहोटी ने तमिलनाडु की जेल में बंद कैदियों के हालात पर तत्कालीन सीजीआई को एक चिट्ठी लिखी थी। सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान लेकर सुनवाई कर चुका है। इससे पहले भी कोर्ट कई दिशा निर्देश जारी कर चुका है।

शासक का दृष्टिकोण

अरब में दूर–दूर तक फैले हुए साम्राज्य की शासक एक महिला थी। उसके साम्राज्य में हर ओर खुशहाली छाई थी। वह समय–समय पर अपनी प्रजा के बीच जाकर उनकी सुख–शांति की खबर लेती रहती थी। एक बार जब वह राज्य भ्रमण करके लौटी तो एक राज्य अधिकारी उनसे बोला, 'महारानी, मैंने इस भ्रमण के दौरान देखा कि चारों ओर लोगों को आपकी न्यायप्रियता, निष्पक्ष व्यवस्था एवं सेवा–भाव से पूर्ण संतोष है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार आपकी आलोचना करते हैं। ऐसे लोगों को दंडित करना जरूरी है।' इसपर साम्राज्ञी गंभीर होकर बोलीं, 'मैं एक बड़े साम्राज्य की मलिका हूं। प्रजा मेरा सम्मान करती है और मुझे अपने दुख से अवगत कराती रहती है। मेरा एक इशारा आलोचकों का मुंह बंद करने के लिए काफी है। लेकिन ऐसे लोगों को दंडित करके हम अपना समय और शांति क्यों नष्ट करें। वैसे भी इस दुनिया में कोई भी कितना ही अच्छा क्यों न हो, लोगों को उसकी आलोचना करने का पहलू मिल ही जाता है। मुझे स्वयं पर पूर्ण विश्वास है, इसलिए मैं उन लोगों की आलोचना से बेवजह क्यों डरूं। वैसे भी एक शासक को यही दृष्टिकोण अपनाना चाहिए कि वह आलोचनाओं की तरफ ध्यान न देते हुए अपने काम को ईमानदारी व न्यायप्रियता से करता चले। ऐसे में शासक के कार्य को देखकर आलोचकों के मुंह स्वयं बंद हो जाएंगे। उसे इन आलोचकों के खिलाफ कुछ करने की जरूरत ही नहीं।' सम्राज्ञी की बात सुनकर राज्य अधिकारी बोला, 'महारानी जी, आज हमें आपकी सफलता का सूत्र पता चल गया है। निश्चित रूप से आलोचनाओं से घबराकर व्यक्ति अपने सामान्य कार्य में भी व्यवधान उत्पन्न कर देता है। इसलिए मैं आपकी बात से पूर्णतया सहमत हूं। हम ऐसे ही कार्य करते रहेंगे जैसे अभी तक करते आए हैं।' इसके बाद वह सम्राज्ञी को सिर नवाकर चला गया।

रेनू सैनी

कभी–कभी ईर्ष्यावष हम दूसरों को गिराना चाहते हैं, परन्तु ऐसा करके हम स्वयं ही गिर जाते हैं।

विज्ञापनों से सरकार को कितना फायदा!

आलोक सोलंकी

सरकारें अपनी छवि चमकाने में जनता के पैसों को विज्ञापनों पर बर्बाद करती हुई दिख रही हैं। सरकारें केंद्र या राज्य में किसी भी दल की हो। सरकारी योजना और प्रचार के नाम पर जनता का धन बर्बाद करने में कोई भी दल पीछे नहीं। मीडिया के विभिन्न माध्यमों को सरकार की ओर से ऐसे विज्ञापन दिए जाते हैं जिनका असली मकसद सरकारी योजनाओं कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाना है परन्तु सरकारो का अब असली मकसद इन अपनी कल्याणकारी नीतियों को जनता तक पहुंचाना नहीं बल्कि अपनी पार्टी और अपने पार्टी के नेताओं का महिमामंडन करना होता है। ये पैसा जनता से टैक्स लगाकर जुटाया जाता है।

हमारे देश में विज्ञापनो पर जनता का पैसा लुटाने की प्रक्रिया राजग सरकार के समय से हो गई थी। उस समय सता में बीजेपी ने शाइनिंग इंडिया के जरिए जमकर जनता के पैसे से अपनी छवि को चमकाया। आगे चलकर यूपीए भी उसी दिशा में बढ़ी। इस दौरान तो जनता के पैसे से सतारूढ़ पार्टी और उसके नेताओं को फ्री में प्रचार पाने की होड़ लग गई। 2004, 2005 से 2014, 2015 के बीच यूपीए सरकार ने 6000 करोड़ रुपये अपनी छवि चमकाने में लगा दिए।

अपने चुनाव वर्ष के आखिरी 2 से 3 वर्ष में ही काग्रेस सरकार ने जनता के टैक्स के 2000 करोड़ रुपये अपनी छवि चमकाने में फूंक दिए जबकि हमारी वर्तमान सरकार ने अपने पहले वर्ष में ही विज्ञापनों पर 1000 करोड़ रुपये फूंक दिए। केंद्र सरकार की महत्वकांक्षी योजना स्वच्छ भारत के विज्ञापनों पर पहले पहले वर्ष ही 100 करोड़ खर्च कर दिए। देश के अधिकतर जिलों में देखने से ही पता चल जाता है कि वहां के अधिकारी और जनता स्वच्छता के प्रति कितने गंभीर हैं। स्वच्छता के प्रति लोग जागरूक हुए हों या नहीं, अधिकरियों ने इससे पब्लिसिटी का जरिया जरूर बना लिया।

जिस देश में 19 करोड़ लोग कुपोषण का शिकार हों, जिन्हें दो वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल हो, वहां विज्ञापनों पर इस तरह जनता के पैसे को बहाना कहां तक उचित है। यह प्रवृत्ति केंद्र सरकार तक सीमित नहीं। राज्य सरकारें भी वही हथकंडे अपनाती हैं राज्य में। सतारूढ़ पार्टियों द्वारा चलाई जा रही योजनाएं जनता तक पहुंचे न पहुंचे, उनकी पार्टी और नेताओं को पब्लिसिटी जरूर मिलनी चाहिए।

मिसाल के तौर पर अति छोटे राज्य में शुमार दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए। यहां पर इमानदार के तौर पर अपने आप को प्रचारित कर रही आप की सरकार है जिसका जन्म एक आंदोलन के जरिए हुआ था। इसका मुख्य उददेश्य जनता के धन की बर्बादी रोकना था परन्तु इस सरकार ने आते ही प्रचार का भारी भरकम 540 करोड़ रुपये बजट रखा जो किसी भी बड़े राज्य से अधिक है तथा यह बजट केन्द्र से आधा है। हालांकि इतने भारी भरकम बजट का मुख्य उददेश्य जनता तक अपनी जन कल्याणकारी नीतियों को पहुंचाना होना चाहिए परन्तु उन्होंने इस पैसे का उपयोग अपनी पार्टी और अपने नेता के प्रचार में खर्च किया।

माँ...

डा. प्रज्ञा 'खुशी'

तुम प्यारी हो सुन्दर हो सबसे अच्छी हो तुम माँ
हम बच्चों को जीवन देकर बन गयी तुम तो देवी माँ।
ईश्वर सब करता है ऐसा सुनते आये है हम सब
हमको सब कुछ दिया है ऐसे जैसे तुम ही ईश्वर माँ।
सारा दर्द अकेले सह कर सब कष्टों से खुद ही लड़कर
अपने लहू को दूध बनाकर सींचा तुमने हमको माँ।
बच्चे करें क्रिया कोई भी कभी नहीं अकुलाती है
खुद गीले में सोकर भी सूखे में हमें सुलाती माँ।
ऊँगली पकड़ी चलना सिखाया पैरों को थमना सिखाया
अपने पैरों के छालों को कभी नहीं दिखलाया माँ।
दुनियाँ की सब रश्में निभाई फिर भी सबसे गाली खाई
खड़ी रही चट्टान के जैसे कितनी शक्तिशाली माँ।
घर बाहर की जद्दोजहद में अपना जीवन भूल गयीं
रोज मिली एक नई चुनौती जिससे लड़ती आई माँ।
अपने दिल के टुकड़ों को एक नया परिवार दिया
संस्कार तो दिए बहुत किस्मत न दे पायी माँ।
हमने जब वो सहा तो समझा दर्द तुम्हारा सारा माँ
एक फरिश्ता होती है इस दुनियां में सबकी माँ।

किसी दूसरे व्यक्ति को विपत्ति में देखकर हंसना आपकी अज्ञानता दर्शाता हैं।

कोलकाता हाईकोर्ट जज ने लगाया आरोप

सुप्रीम कोर्ट में 'ऊंची जाति' वाले जजों की चलती है

दु:खद लेकिन हकीकत

जस्टिस कर्णन ने सवाल किया है कि SC को उनके खिलाफ एक्शन लेने का क्या हक है। सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट की अवमानना करने से संबंधित नोटिस कर्णन को भेजा था कर्णन ऐसा नोटिस पाने वाले हाईकोर्ट के पहले सिटिंग जज हैं।

कोलकाता : सुप्रीम कोर्ट द्वारा अदालत की अवमानना का नोटिस मिलने के बाद कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस सीएस कर्णन ने सर्वोच्च न्यायालय के किसी सिटिंग जज को नोटिस थमाने के अधिकार पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। साथ ही उन्होंने एक बार फिर आरोप लगाया है कि ऊंची जाति के जज, एक दलित जज से छुटकारा पाने के लिए अपने अधिकारों का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं।

आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जस्टिस कर्णन वही हैं जो 2011 से पूर्व और मौजूदा जजों पर आरोप लगाते आ रहे हैं कि उनके (कर्णन के) दलित होने की वजह से उन्हें दूसरे जजों द्वारा प्रताड़ित किया जाता रहा है। 2016 में जस्टिस कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम द्वारा उनके कोलकाता हाईकोर्ट में ट्रांसफर किए जाने के आदेश पर कहा था कि उन्हें दुख है कि वह भारत में पैदा हुए हैं और वह ऐसे देश में जाना चाहते हैं जहां जातिवाद न हो।

सुप्रीम कोर्ट के सब्र की सीमा तब पार हो गई जब इसी साल जनवरी में कर्णन ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर सुप्रीम कोर्ट और मद्रास हाइकोर्ट (जहां वह पहले पदस्थ थे) के जजों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने अपनी चिट्ठी में मौजूदा और सेवानिवृत्त हो चुके 20 जजों के नाम भी लिखे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी को जस्टिस कर्णन को नोटिस जारी किया और पूछा कि क्यों न इसे कोर्ट की अवमानना माना जाए। गौरतलब है कि इस तरह का नोटिस पाने वाले कर्णन हाईकोर्ट के पहले सिटिंग जज हैं।

अब कर्णन ने इस नोटिस के जवाब में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को हाईकोर्ट के मौजूदा जज को नोटिस भेजने का क्या अधिकार है। कर्णन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उनके खिलाफ अवमानना का मामला संसद में सरका सकता है।

अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने दावा किया है कि सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के जवाब में कर्णन द्वारा लिखी गई चिट्ठी की कॉपी उनके पास उपलब्ध है। अखबार के मुताबिक कर्णन ने लिखा है कि यह आदेश किसी तर्क का पालन नहीं करता इसलिए इसका क्रियान्वयन के लिहाज से ठीक नहीं है। इस आदेश के लक्षण साफतौर पर दिखाते हैं कि किस तरह कानून ऊंची जाति के जजों के हाथ में है और वह अपनी न्यायिक ताकतों को अनुसूचित जाति जनजाति के जज से छुटकारा पाने के लिए इसका बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए आठ फरवरी 2017 को जारी किए गए स्वयं प्रेरित अवमानना आदेश कानून के तहत नहीं टिक सकता।

बता दें कि कोलकाता हाईकोर्ट में पदस्त जस्टिस कर्णन को मार्च 2009 में मद्रास हाईकोर्ट का एडिशनल जज नियुक्त किया गया था। इसके बाद वह लगातार जजों और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अपने अलग अलग बयानों की वजह से सुर्खियों में बने रहे। सबसे ज्यादा चर्चा में वह तब आए जब उन्होंने 2011 में अनुसूचित जाति राष्ट्रीय आयोग को चिट्ठी लिखी कि उनके दलित होने की वजह से वह अन्य जजों द्वारा उत्पीड़ित किए जाते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दूसरे जज उन्हें छोटा साबित करने पर तुले होते हैं। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा था कि किस तरह एक शादी के कार्यक्रम में एक दूसरे जज ने अपने पैरों को यह सोचकर थोड़ा दूर कर लिया कि कहीं कर्णन का पैर उनसे छू न जाए। कर्णन की बतौर जज नियुक्ति करने की सिफारिश करने वाले हाईकोर्ट कोलेजियम के तीन में से एक जज ने पिछले साल सार्वजनिक तौर पर कर्णन की नियुक्ति करने के लिए माफी मांगी थी। **नीरज बंसल**

आप अपने जीवन का महत्व समझकर चलो तो दूसरे भी महत्व देंगे।

हेरा–फेरी, तुम्हारा–हमारा

महेंद्र पाण्डेय

आम बजट 2017 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आयकर (Income TaX) देयकर्ता के लिए टैक्स स्लैब में परिवर्तन किए। चालू वित्तीय वर्ष (2016–17) के लिए जो इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल करेंगे, वे मौजूदा रेट्स और स्लैब के हिसाब से है। लेकिन, अगले आंकलन वर्ष यानी 2018–19 के लिए टैक्सदाताओं को जेटली ने कुछ राहत दी है। जहां पहले ढाई लाख रुपए से लेकर पांच लाख रुपए तक की सालाना आय पर 10 फीसदी टैक्स लगता था, अब यह टैक्स 5 फीसदी लगेगा। वहीं, ढाई लाख तक आय पूरी तरह से टैक्स मुक्त है। मोदी सरकार के इस चौथे बजट (Union Budget) में 50 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की आय वालों पर 10 फीसदी का सरचार्ज लगाया गया है जो अब तक नहीं था।

आइए एक नजर में जानें Budget 2017-18 में ऐलान किए गए नियमों के मुताबिक इनकम टैक्स संबंधी वे नियम जो अप्रैल 2017 से लागू हैं। आकलन वर्ष रहेगा 2018–19 जनरल कैटेगरी के तहत आने वालों के लिए 60 साल तक आयु वाले किसी भी व्यक्ति की आय यदि सालाना 2.5 लाख रुपए से अधिक है तब वह टैक्स छूट के दायरे से बाहर माना जाएगा। यानी, केवल 2.5 लाख रुपए तक की आय ही करमुक्त है। इसके बाद 5 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले व्यक्ति को 5 फीसदी टैक्स चुकाना होगा। साथ ही, 5 लाख रुपए तक की कर योग्य आय पर पहले 5 हजार रुपए का रिबेट मिलता था जोकि अब घटाकर 2500 रुपए कर दिया गया है और यह 3.5 लाख रुपए तक की कर योग्य आय पर मिलेगा। इसका मतलब हुआ कि यदि किसी शख्स की सालाना आय 3 लाख रुपए है तो उसकी टैक्स लायबिलिटी जीरो होगी। इसे ऐसे समझें–50 हजार रुपए पर 5: टैक्स का मतलब हुआ 2500 रुपए, जिस पर मिली 2,500 रुपए की छूट, तो ऐसी स्थिति में कोई कर नहीं देना होगा।

5 से 10 लाख रुपए की इनकम पर 20 फीसदी का इनकम टैक्स होगा और 10 लाख रुपए से अधिक की आय पर 30 फीसदी का इनकम टैक्स लागू होगा। लेकिन यदि आपकी आय 50 लाख रुपए से ज्यादा है (सालाना) लेकिन 1 करोड़ रुपए से कम है, तब आपको 30 फीसदी टैक्स तो देना ही होगा साथ ही 10 फीसदी का सरचार्ज भी देना होगा। इसके अलावा । यदि करयोग्य आय 1 करोड़ रुपए है तब सरचार्ज बढ़कर 15 फीसदी हो जाएगा। यह बढ़ा हुआ 5 फीसदी सरचार्ज एजुकेशन सेस और हायर एजुकेशन सेस है।

सीनियर सिटीजन (60 से 80 आयुवर्ष के लोगों के लिए)

वरिष्ठ नागरिक जोकि 0 से 3 लाख रुपए सालाना आय के दायरे में आते हैं, उन पर कोई आयकर देनदारी नहीं बनती। 3 से 5 लाख रुपए तक की आय पर 5 फीसदी की दर से टैक्स लागू होगा। 5 से 10 लाख रुपए तक की आय और 10 लाख रुपए से अधिक की आय पर जनरल कैटेगरी के लिए लागू टैक्स रेट और सरचार्ज सीनियर सिटीजन पर भी लागू होंगे। सुपर सीनियर सिटीजन (80 साल की आयु से अधिक के लोगों के लिए) वे वरिष्ठ नागरिक जिनकी आयु 80 साल से अधिक है वे इस कैटेगरी में आते हैं। उनके लिए 5 लाख रुपए तक की आय पूरी तरह से टैक्स फ्री है। बाकी सभी टैक्स स्लैब वही लागू होंगे जोकि जनरल कैटेगरी पर लागू हैं। मौजूदा व्यवस्था में 2,50,000 रुपये वार्षिक तक करयोग्य आय वालों को कोई आयकर नहीं देना होता, जबकि 2,50,001 से 5,00,000 रुपये तक 10 फीसदी टैक्स, 5,00,001 से 10,00,000 रुपये तक की करयोग्य आय वालों को 20 फीसदी टैक्स, और 10,00,001 तथा उससे अधिक कमाने वालों को 30 फीसदी टैक्स देना पड़ता है। यदि आप दूसरे होम लोन की तैयारी कर रहे हैं तो जान लें यह नया टैक्स नियम क्योंकि दूसरे होमलोन पर केंद्र सरकार नहीं देगी यह लाभ। इसे आप इस चार्ट द्वारा भी समझ सकते हैं।

बिना दांत वाला शेर

हमारे यहां चुनाव आयोग बिना दांत का शेर हो गया है, वैसे अभी पुलिस सुधार से संबंधित एक याचिका में उच्चतम न्यायायल ने यह कहते हुए तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया कि हमारी कोई सुनता ही नहीं है तो ऐसी हालत में चुनाव आयोग से बहुत ज्यादा उम्मीद करने की कोशिश नहीं की जा सकती है। अभी चुनाव में जिस तरह से बोल बोले गए यह एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। जबकि न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि धर्म, जाति, सम्प्रदाय के नाम पर वोट मांगना गलत है लेकिन इसी को आधार मान कर वोट मांगा गया और जनता को सड़े फलों की टोकरी में से फल चुनने के लिए कहा गया अब जनता की मजबूरी है कि वह कोई भी फल चुनेगी उसे फल सड़ा ही मिलेगा क्योंकि टोकरी में सभी फल सड़े हैं यही हाल भारतीय प्रजातंत्र का हो गया है। आने वाला समय और खराब होने वाले हैं पहले जैसे डाकू लूटते थे और कुछ गरीबों को दान करके मसीहा बन जाते थे वही हाल अब भारतीय राजनीतिक माफिया भी कर रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक बार जेल से चुनाव लड़कर विधायक बने तिवारी की न्यूज बीबीसी ने प्रसारित की भी अब तो ऐसे नेताओं की बाढ़लग गई है।

अच्छा संग आगे बढ़ने का बल और हिम्मत देता है।

हार का मंथन

आखिरकार उत्तर प्रदेश में वही नतीजे आए जिसकी बहुत लोगों को उम्मीद नहीं थी। लगभग 27 सालों से सत्ता से बाहर रही कांग्रेस पार्टी हो या 2014 के लोकसभा में मिली अभूतपूर्व हार से आहत बहुजन समाज पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दमदार व्यक्तित्व पर लहराती बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी पर सम्पूर्ण कब्जा पा लेने के बाद अति–उत्साहित अखिलेश यादव (जिनको कांग्रेस के राहुल गांधी का साथ मिला) सभी को इस विधानसभा चुनाव में पूरी उम्मीद थी कि इतिहास तो रचा जाएगा... और इतिहास तो रच ही दिया गया। बीजेपी के घोर समर्थक भी पार्टी के 200 के करीब का आंकड़ा पाने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से संप्रदाय, जाति या क्षेत्र के सीमाएं तोड़ते हुए कुल वोट का 40 प्रतिशत से भी ज्यादा पाकर बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की सत्ता हासिल की है, उससे प्रदेश के लोगों और राजनीतिक माहौल के बारे में नई परिभाषाएं गढ़ने की जरूरत महसूस हो रही है।

अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। अखिलेश और राहुल गांधी ने अपने गठबंधन को दो युवाओं की दोस्ती के रूप में पेश किया और नारा दिया कि 'यूपी को ये साथ पसंद है।' लेकिन प्रदेश को ये साथ पसंद नहीं आया, यह स्पष्ट हो गया है। 'तीसरे खिलाड़ी' की तरह चुनाव मैदान में उतरी बहुजन समाज पार्टी को तो लगता है कि प्रदेश की जनता के बड़े हिस्से ने पूरी तरह से नकार दिया है। यहां तक कि यदि जनसंख्या में बसपा के स्थापित समर्थकों के समुदाय की हिस्सेदारी को ही आधार माना जाए तो शायद उस समुदाय ने भी बहन मायावती से मुंह मोड़ लिया है।

चुनाव से पहले कयास लगाए जा रहे थे कि गठबंधन द्वारा बिहार के चुनावी नतीजे दोहराए जा सकते हैं। नोटबंदी का नुकसान झेल रही भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई करिश्मा नहीं दिखला पा रहे हैं और लोगों को अखिलेश द्वारा शुरू किए गए काम (लखनऊ की मेट्रो, एक्सप्रेसवे आदि) इतने पसंद हैं कि प्रदेश के इतिहास में दशकों बाद कोई सरकार दोहराई जा सकती है। लेकिन न नोटबंदी, न गठबंधन और न ही दलित–मुस्लिम गठजोड़ लोगों को प्रभावित कर पाया और मोदी का जादू फिर चल ही गया।

जैसे–जैसे नतीजे आते जा रहे थे, वैसे–वैसे ही एक समुदाय के लोगों में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इस समुदाय के एक वरिष्ठ नागरिक ने यहां तक कहा कि उन्हें अब लखनऊ में रहने के बारे में सोचना पड़ेगा, वहीं कांग्रेस के एक बहुत वरिष्ठ नेता ने एक कार्यक्रम में प्रदेश के लोगों की समझदारी पर ही सवाल खड़े कर दिए। अपनी प्रतिक्रिया में मायावती ने भाजपा पर ठीकरा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से छेड़छाड़ का आरोप लगा दिया। केवल सपा के प्रतिनिधियों ने ही ईमानदारी से स्वीकार किया कि उनकी पार्टी में पिछले कुछ महीनों के घटनाक्रम की वजह से उनकी हार हुई और यह भी माना कि उनकी पार्टी को अपनी गलतियों से सबक लेना होगा।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ अनुमान पहले से ही लगाये जाते रहे हैं, जैसे, यहां जातिवाद का बोलबाला है, यहां बाहुबली राजनीतिक नेता ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, यहां ध्रुवीकरण काम कर जाता है, यहां राष्ट्रीय दलों का महत्व कम होता जा रहा है और क्षेत्रीय, जाति–आधारित दल प्रभावशाली होते जा रहे हैं, और यहां प्रादेशिक क्षेत्र ही मायने रखते हैं। लेकिन भाजपा की इस जीत ने इन सभी अनुमानों को दरकिनार कर कर दिया है। सपा और बसपा के हाशिये पर जाने से यह स्पष्ट है कि पिछड़ी और दलित जातियों के लोगों ने बड़ी मात्रा में भाजपा को समर्थन दिया है। साथ ही, एक राष्ट्रीय पार्टी द्वारा केवल एक राष्ट्रीय नेता (नरेन्द्र मोदी) को आगे रखकर क्षेत्रीय पार्टी के महत्व को एकदम से घटा कर रख दिया है। इसके साथ ही कई मुस्लिम बहुल इलाकों में भाजपा के प्रत्याशी का जीतना यह भी स्थापित करता है कि शायद अल्पसंख्यक वर्ग ने भी बड़ी हद तक भाजपा का समर्थन किया है और ऐसा तब हुआ जब भाजपा ने एक भी मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव में नहीं उतारा था।

जहां तक मायावती का सवाल है, उन्होंने अपनी बौखलाहट में अपनी हार का ठीकरा ईवीएम में छेड़छाड़ पर फोड़ दिया है। यही नहीं, उन्होने यहां तक कहा कि अन्य पार्टियों के समर्पित मतदाताओं का भाजपा के पक्ष में चले जाना किसी के गले नहीं उतर रहा है। गैर भाजपा दलों को अब यह समझना होगा कि जाति और संप्रदाय के इतर लोगों को मोदी के वादे और उनका काम करने का तरीका पसंद आ रहा है। शायद समय आ गया है कि भाजपा और मोदी का तार्किक और अतार्किक विरोध करने के बजाय अन्य राजनीतिक दलों को आत्मनिरीक्षण और मंथन करना चाहिए कि वे भविष्य में अपने को कहां देखना चाहते हैं।

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता समानता और भाई–चारा सिखाये।

बोले सीएम योगी, सूर्य नमस्कार और नमाज एक जैसे

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित योग महोत्सव के दौरान कहा कि योग किसी जाति, धर्म, उम्र और लिंग का मोहताज नहीं है। असल में सूर्य नमस्कार में प्राणायाम की क्रियाएं और नमाज की मुद्राएं एक जैसी हैं।

अगर आप सूर्य नमस्कार करते हुए देखेंगे तो आपको यह वैसे ही लगेगा, जैसे मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं. सूर्य नमस्कार में जितने आसन आते हैं, उसमें जो प्राणायाम की क्रियाएं हैं, वो मुस्लिम भाई जो नमाज पढ़ते हैं, उससे मिलती–जुलती हैं।

इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित उत्तर प्रदेश में योग महोत्सव में बाबा रामदेव के साथ राज्यपाल राम नाईक ने भी शिरकत की. महोत्सव में सीएम योगी ने कहा कि उन्हें योग के कार्यक्रम से खुशी है. उन्होंने कहा कि लोग साधु संतों को भीख नहीं देते हैं. मुझे तो सत्ता सौंप दी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी का धन्यवाद देते हुए सीएम योगी ने कहा कि उन्हीं ने उन्हें सत्ता दी. सरकार के सामने चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन जीवन में सकारात्मक सोच उन्होने मोदी जी से सीखा है। उनकी इसी सोच के कारण देश आगे बढ़ रहा है. अराजकता से उबा. रने का काम 2014 में शुरू हुआ, उसी कारण भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से बढ़ रही है. उन्होंने बताया कि लोकतंत्र में भी नोटबंदी जैसी कार्रवाई हो सकती है।

उन्होंने कहा कि सीएम पद लेने से वह नहीं भागे. अगर वह पद नहीं लेते तो लोग कहते कि जिम्मेदारी से भागे. विधायकों ने मुझे अपना नेता चुना है. मैंने यूपी में सड़क से सदन तक की यात्रा की है, यहां की बहुत जानकारी है. मैं पूरा यूपी घूमा हूं।

मुझे यहां की सभी बीमारियों का पता है. वह यूपी के लिए बड़े फैसले लेने में नहीं हिचकेंगे. उन्हें यूपी से नकारात्मकता का खात्मा करना है. उन्होंने कहा कि पहले संकीर्ण सोच के साथ नेता काम करते थे. कुछ लोगों का योग में नहीं भोग में विश्वास है. 2014 से पहले योग की बात सांप्रदायिकता थी. हम योग को जन–जन तक पहुंचाने का काम करेंगे।

उन्होंने कहा कि भारत ने बल के आधार पर किसी को प्रभावित नहीं किया. जननी जन्मभूमि का हमारा संबंध बना रहेगा. यह देश आतंकवाद और नक्सलवाद का शिकार हुआ. तमाम प्रकार की अरा. जकता इस समय भारत में फैली हुई है. सत्ता के लिए पार्टियों ने यहां राज किया है। उन्होंने बाबा रामदेव के लिए कहा कि उन्होंने योग को घर–घर पहुंचाने का काम किया. वहीं प्रधानमंत्री ने योग को पहचान दिलाने का काम किया। उन्होंने कहा कि योग आत्म अनुशासन की सबसे बड़ी चीज है।

योग करने से मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूती मिलती है. योग करने से व्यक्ति बुढ़ापे तक स्वस्थ रहता है। सीएम योगी ने कहा कि हम सबको तय करना है कि सां. प्रदायिक कौन है. सूर्य नमस्कार में जितने आसन आते हैं, उसमें जो प्राणायाम की क्रियाएं हैं वो मुस्लिम भाई जो नमाज पढ़ते हैं उससे मिलती जुलती हैं. हर जाति, धर्म का व्यक्ति योगिक क्रियाओं को कर सकता है।

साभार : इंटरनेट

मुस्लिम बोले– नमाज और सूर्य नमस्कार एक नहीं

लखनऊ के योग महोत्सव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सूर्य नमस्कार और नमाज की तुलना करने पर पर सियासत शुरू हो गई है। कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं और सियासी दलों ने निंदा करते हुए योगी के इस बयान को हिंदू और मुस्लिम धर्म को तोड़ने की कवायद से जोड़ दिया है। तो कुछ ने योगी के इस बयान की सराहना भी की है।

मुस्लिम धर्मगुरू उमर इलियासी का कहना है कि नमाज और सूर्य नमस्कार दोनों अलग बातें हैं। मुझे लगता है कि योगी ने इन दोनों को जोड़कर हिंदू–मुसलमान दोनों मजहबों को तोड़ने का कवायत की है। कांग्रेस के पीएल पुनिया का कहना है कि नमाज और सूर्य नमस्कार में समानता है। हो सकता है समानता हो, पर दोनों से समान व्यवहार होना चाहिए। दोनों से प्यार मुहब्बत बढ़ने की बात हो। उम्मीद है भविष्य में प्यार मुहब्बत बढ़ेगी।

जेडीयू प्रवक्ता के सी त्यागी ने योगी के इस बयान की सरहाना की है. केसी त्यागी का कहना है कि मुझे खुशी है कि जिम्मेदारी ने उन्हें नर्म दिल बना दिया है। धर्मगुरू मौलाना सुहेब कासमी ने भी योगी के बयान की तारीफ करते हुए कहा कि पूजा नमाज जैसी सभी इबादतें एक जैसी हैं। ईश्वर एक है और पूजा एक ही के लिए सब करते हैं। योगी का ये बयान एक अच्छा बयान है।

यदि हम भविष्य के बारे में भयभीत हो जाएंगे तो वर्तमान में प्राप्त अवसरों को खो देंगे।

जीएसटी को लोकसभा की मंजूरी

देश के लिए सबसे बड़ा आर्थिक सुधार बताए जा रहे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी से जुड़े 4 अहम विधेयक बुधवार को लोकसभा से पारित हो गए। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी को क्रांतिकारी कदम बताया तो पीएम मोदी ने नया नारा दिया– 'नया साल, नया कानून, नया भारत'। जीएसटी से देश के वित्तीय ढांचे में ये 10 बड़े बदलाव आएंगे।

1. जीएसटी लागू होने के बाद पूरे देश में एक टैक्स प्रणाली होगी। अभी तक कुछ टैक्स लगाने का अधिकार केंद्र औैर कुछ टैक्स लगाने का अधिकार राज्यों को था।

2. राज्य और केंद्र मिलकर सामान और सेवाओं पर टैक्स लगाएंगे। इससे देश भर में वस्तुओं के दाम कम होंगे। वित्तमंत्री ने कहा कि जीएसटी से आम लोगों पर अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जा रहा है। साथ ही सेहत पर खराब असर डालने वाले सामानों और लग्जरी प्रॉड्क्स पर ज्यादा टैक्स लगाया गया है।

3. जेटली ने कहा कि जीएसटी के कई टैक्स रेट होना ठीक है। हवाई चप्पल और बीएमडब्ल्यू पर एक समान टैक्स नहीं लगाया जा सकता है। संसद और राज्यों की विधानसभाओं को गुड्स और सर्विसेज पर टैक्स लगाने का अधिकार होगा।

4. जीएसटी काउंसिल में 32 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। संविधान संशोधन के तहत जीएसटी के तहत पहले पांच साल में किसी राज्य को घाटा होगा, तो उसकी व्यवस्था की जाएगी। टैक्स को लेकर अगर दो राज्यों में विवाद होता है, तो आम सहमति से फैसला लिया जाएगा। जम्मू एवं कश्मीर राज्य को जीएसटी कानून के दायरे में नहीं लाया गया है।

5. जीएसटी लागू होने से टैक्स में चोरी आसान नहीं होगी।

6. जीएसटीके लागू होने के बाद देश भर में गुड्स एवं सर्विसेज की मूवमेंट आसान होगी।

7. जीएसटी के लागू होने से आपूर्ति क्षमता बेहतर होगी।

8. इस नई कर व्यवस्था से एकरूपता आएगी और ग्राहकों के लिए फायदेमंद साबित होगा। जीएसटी से ऑनलाइन लेनदेन बढ़ेगा और इससे कर देने वालों का दायरा बढ़ेगा। इसका ईमानदार करदाताओं को फायदा मिलेगा।

9. विश्व बैंक के एक अध्ययन में कहा गया है कि जीएसटी लागू होने से GDP में 2% का इजाफा होगा।

10. टैक्स दरों की चर्चा करते हुए लोकसभा जेटली ने कहा, अभी हमारे पास कई टैक्स ब्रैकेट्स हैं. ये टैक्स स्लैब्स 0%, 5%, 12%:, 18% और 28% हैं. खाने–पीने की अहम चीजों पर 0% टैक्स, जबकि नुकसानदेह या लग्जरी चीजों पर अधिक टैक्स रखा गया है। **एजेंसी**

क्या महंगा होगा और क्या सस्ता...

लोकसभा में चली लंबी बहस के बाद आखिरकार जीएसटी बिल पास हो गया. लेकिन विपक्ष इस बिल में हुए संशोधन से अभी भी नाखुश है. विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने उनके द्वारा पेश किये संशोधन को दरकिनार कर दिया है।

आपको बता दें कि सरकार ने जीएसटी विधेयक 2017 में पांच संशोधनों के साथ पास किया है. ऐसा दावा किया जा रहा है कि जीएसटी के अमल में आने से तरह–तरह के टैक्स के बजाए सिर्फ जीएसटी ही लागू होगा और पूरा देश एक बड़ा बाजार बन जाएगा. आइए जानते हैं इस बिल के बाद क्या असर पड़ेगा बाजार में।

लोकसभा में बिल पेश करते समय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी से देश में टैक्स टेररिज्म का खात्मा होगा।

लोकसभा में जीएसटी बिल पर चर्चा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी की 4 दरें होंगी और इसकी अधिकतम सीमा 28 फीसदी की होगी. इतना ही नहीं लग्जरी सामान पर अलग से सेस भी लगेगा।

जीएसटी मल्टीपल टैक्सेशन स्लैब रखे गए हैं. खाने–पीने की चीजें 0 फीसदी टैक्स स्लैब में आएंगी। दूसरा टैक्स स्लैब 5 फीसदी का होगा वहीं तीसरा स्लैब 12–18 फीसदी का होगा जबकि 28 फीसदी अधिकतम टैक्स स्लैब होगा।

लग्जरी स्लैब में तंबाकू, महंगी गाड़ियां आएंगी. लग्जरी स्लैब के 2 हिस्से होंगे, सेसटैक्स. लग्जरी/तंबाकू उत्पादों पर 28 फीसदी के साथ सेस भी लगेगा।

पूरे देश में किसी सामान की एक ही कीमत होगी. एक राज्य से दूसरे राज्य में तस्करी रुकेगी और जीएसटी से उत्पाद की लागत में कमी आएगी. जीएसटी से टैक्स का ढांचा आसान होगा और सरकार की टैक्स से कमाई बढ़ेगी। जीएसटी से टैक्स चोरी पर शिकंजा कसेगा।

जीएसटी के लागू होने से दोपहिया वाहन, छोटी कारें, फैन, वॉटर हीटर, कूलर और फिल्में देखना सस्ता हो जाएगा। हालांकि जीएसटी से फोन बिल, होटल में खाना–पीना, हवाई टिकट, रेल टिकट, ट्रक और टेंपो महंगे हो जाएंगे।

उधर दूसरी ओर कांग्रेस के नेता वीरप्पा मोइली ने कहा कि जीएसटी यूपीए सरकार का बिल था. इसमें बीज. पी ने बतौर विपक्ष अड़ंगा लगाया. उन्होंने कहा कि जीएसटी के मौजूदा ढांचे में कई दिक्कतें हैं. इसमें टैक्स अधिकारियों की ज्यादती और भ्रष्टाचार के लिए कमियां रह गई हैं। **एजेंसी**

यदि आप अस्वस्थ हैं तो धैर्य रखिए तथा मन को स्वस्थ बनाए रखिए।

स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत

जमे–जमाए सार्वजनिक सेवा तंत्र को अब निजी क्षेत्र के हवाले किया जा रहा है. स्कूल शिक्षा का हाल हम देख ही चुके हैं। अब स्वास्थ्य क्षेत्र भी इसी ओर जाता दिख रहा है. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से पेश की गई नई स्वास्थ्य नीति भी इस पर कहीं नियंत्रण करती नहीं दिख रही है. भारत जैसे देश में, जहां 3/4 आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रही हो, उस समाज के लिए सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं होना निहायत जरूरी हैं, लेकिन हो यह रहा है कि स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की सहज अनुपलब्धता के चलते बीमार लोगों को इस पर बहुत खर्च करना पड़ रहा है। इसके कारण हर साल एक बड़ी आबादी गरीबी की ओर जा रही है, और विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक यह संख्या लगभग पांच प्रतिशत है।

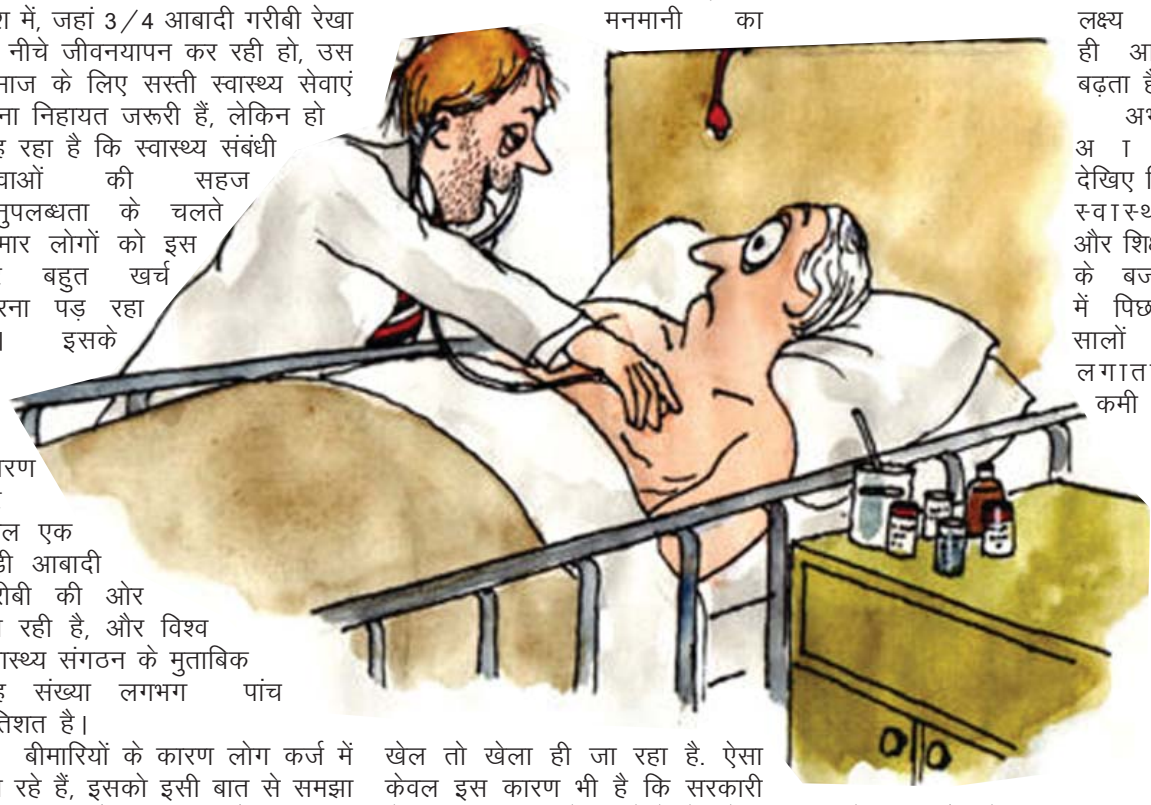

बीमारियों के कारण लोग कर्ज में जा रहे हैं, इसको इसी बात से समझा जा सकता है कि टीबी जैसी भयंकर बीमारी का पूरी तरह निःशुल्क इलाज होने के बावजूद प्राइवेट अस्पताल बड़े पैमाने पर फल–फूल रहे हैं. इसे पिछले दिनों सरकार द्वारा दिल में लगाए जाने वाले स्टेंट की कीमतों के रेगुलेशन से भी समझा जा सकता है। मामला केवल एक स्टेंट भर का नहीं है। नई स्वास्थ्य नीति में इसे माना भी गया है, लेकिन लोगों का खर्च कम करने का रास्ता केवल और केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती से होकर आता है. हमारा पूरा जोर स्वास्थ्य बीमा आधारित देखभाल पर अधिक दिखता है, और बीमा निजी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी संजीवनी की तरह का काम करता है. दरअसल, स्वास्थ्य सेवाओं में निजी क्षेत्र की निगरानी और नियंत्रण अब भी बेहद लचीला है। कई स्वास्थ्य मानक तो ऐसे भी हैं, जिनकी कोई रिपोर्टिंग प्राइवेट अस्पताल सरकारी अस्पताल को अनिवार्यतरू नहीं करते हैं. ऐसे में मनमानी का खेल तो खेला ही जा रहा है. ऐसा केवल इस कारण भी है कि सरकारी सेवा तंत्र अपना भरोसा लोगों से खोता जा रहा है या जानबूझकर खोते जाने दिए जा रहा है।

पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने अपने भाषण में किसी भी बेहतर सेवा के लिए चार प्रमुख चीजों को जिम्मेदार ठहराया था. ये थीं – क्लैरिटी ऑफ विजन, क्लैरिटी ऑफ डिजाइन, क्लैरिटी ऑफ इन्सेन्टिव और क्लैरिटी ऑफ इम्प्लिमेंटेशन, लेकिन क्या क्लैरिटी ऑफ इंटेन्शन सबसे जरूरी नहीं है।

सवाल यहीं आकर खड़ा हो जाता है। सवाल यह भी है कि किसी भी विचारधारा की सरकारें गद्दी पर आसीन हों, क्या अंतरराष्ट्रीय राजनीति और बाजार की ताकतें उसमें अपनी भूमिका निभाती हैं. नई स्वास्थ्य नीति में तमाम लोगों के साथ हेल्थ केयर इंडस्ट्री से भी भागीदारी की बात की गई है. उद्योग से हम सेवा करने की उम्मीद नहीं करते हैं. वह तो लाभ कमाने के लक्ष्य से ही आगे बढ़ता है। अभी आप देखिए कि स्वास्थ्य और शिक्षा के बजट में पिछले सालों में लगातार कमी होती रही हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस नीति में जोर इस बात पर है कि कोशिश यह होनी चाहिए कि हम बीमार ही नहीं पड़ें। यह बात सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर भी लागू होती है। यह काम हवा में नहीं हो सकता। सरकार को अब भी जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य सेवा बचाने के लिए खर्च करना होगा, वहीं भारत की आबादी को बेहतर रोजगार, पोषण, शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी। तभी सही मायनों में स्वच्छ भारत के साथ स्वस्थ भारत बनाया जा सकेगा।

जो बात आपकी खुशी को नष्ट करने वाली हो–उसे कभी न सुनो।

...और उखड़ गई यादव ब्रिगेड

भारतीय जनता पार्टी ने उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनावों में प्रचंड बहुमत हासिल करते हुए सभी अनुमानों को गलत साबित कर दिया। यूपी जैसे बड़े प्रदेश में बीजेपी की जीत के बड़े मायने हैं और इसका असर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों में स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। विरोधी पार्टियों को समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर कमी कहां रह गई। खासतौर से समा. जवादी पार्टी (SP) और कांग्रेस तो गठबंधन के बाद से जैसे जीत के प्रति आश्वस्त थे, लेकिन यह भी उनके काम नहीं आया और उनको अब तक की करारी हार झेलनी पड़ी। वैसे तो बीजेपी की जीत में कई अहम कारक हैं और विरोधियों के बीच अनिश्चितता के माहौल ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई, लेकिन उसका जनता के बीच पहुंचाया गया एक संदेश ऐसा कारक साबित हुआ कि यूपी की जनता ने कांग्रेस, सपा और बीएसपी से दूरी बना ली और उन्होंने बीजेपी के पास जाने में ही भलाई समझी। साबित किया कि अखिलेश को है केवल 2 की ही चिंता।

ओ बापू सत्ता के लिए तू तो हानिकारक है

विरोधी दलों में जारी उठापटक के बीच बीजेपी (BJP) एक ऐसे बड़े संदेश को जनता के बीच स्थापित करने में सफल रही, जिसने गेमचेंजर की भूमिका निभाई। उसके कार्यकर्ताओं ने गुप्त तरीके से इसे लक्षित वर्ग तक पहुंचाना जारी रखा। हालांकि पीएम मोदी ने इशारों–इशारों में प्रचार के अंतिम दौर में इसका जिक्र किया था। यह संदेश था कि सत्ताधारी समाजवादी पार्टी को केवल दो की ही चिंता है– यादव और मुसलमान! इतना ही नहीं उसने इसके लपेटे में कांग्रेस और बसपा को भी ले लिया।

गौरतलब है कि उत्तरप्रदेश में बेरोजगारी की बड़ी समस्या है और अखिलेश यादव के शासनकाल में नौकरियों में यादवों का बोलबाला देखा गया। ज्यादातर विभागों में इसी जाति के लोगों को नियुक्ति दी गई और अन्य वर्ग इससे वंचित रह गए। भले ही वह पिछड़े थे। UPPSC की परीक्षा में यादव जाति के प्रतिभागियों को मिली बड़ी सफलता ने इस तथ्य को और स्थापित कर दिया। बाद में इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई और UPPSC चेयरमैन डॉ। अनिल यादव के कामकाज के तौर तरीकों पर भी आरोप लगे। बाद में कोर्ट ने बोर्ड के चेयरमैन को ही हटा दिया। इससे जनता के बीच यह संदेश गया कि सपा के सत्ता में आने से अन्य वर्गों का कल्याण नहीं होगा और बीजेपी ने इसे ही भुना लिया।

सपा सरकार पर मुसलमानों पर भी अधिक ध्यान देने का आरोप लगा, जिससे एक हद तक हिंदू भी एकजुट होकर बीजेपी की ओर चले गए। कांग्रेस से गठबंधन होने के बाद भी उन्हें इसका फायदा नहीं मिला, क्योंकि कांग्रेस पर तो पहले से ही मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप थे। विकास के नाम पर 'काम बोलता है' का नारा भी फेल रहा, क्योंकि कई लोगों का मानना है कि लखनऊ को छोड़कर कहीं भी विकास कार्य ज्यादा नहीं हुए। खुद उनके विज्ञापन भी लखनऊ केंद्रित रहे।

दूसरी ओर बसपा सरकार के दौरान मायावती पर जाटवों को ही वरीयता देने का आरोप लग चुका था। मतलब जनता के बीच यह संदेश गया कि मायावती वापस सत्ता में आने पर फिर वही करेंगी। फिर क्या था बीजेपी के चुनाव प्रबंधकों और प्रचारकों ने जनता के बीच इस तथ्य को स्थापित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा दल है जो सबके बारे में सोच रहा है और उसी को वोट देने से सबका कल्याण होगा। इससे अखिलेश यादव और राहुल गांधी को जनता के बीच युवाओं के प्रतिनिधि के रूप में स्थापित करने का कांग्रेस और सपा का प्रयास पूरी तरह फेल हो गया। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की जनता के बीच पैठ बनाने के लिए न केवल अपने संगठन को मजबूत बनाया, बल्कि उसने बिहार वाली गलती नहीं दोहराई और चुनाव को विकास जैसे मुद्दे से नहीं भटकने दिया। कुछ विवाद भी हुए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित उसके स्टार प्रचारकों ने इनके साथ ही जनता का ध्यान विकास की ओर केंद्रित रखा और ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली। (एजेंसी)

हर एक के विचार और स्वभाव में अन्तर होता है लेकिन स्नेह में अन्तर नहीं होना चाहिए।

सीएम पद के उम्मीदवार गोम्स भी नहीं दर्ज कर पाए जीत

गोवा में हुए विधानसभा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी ने एलविस गोम्स को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उसे इन चुनावों में एक भी सीट पर जीत नसीब नहीं हुई। आप ने एलविस गोम्स को दक्षिणी गोवा की कुनको. लिम सीट से टिकट दिया था। उन्हें कांग्रेस के क्लाफासियो डायस ने हरा दिया।

पूर्व नौकरशाह एल्विस गोम्स ने जुलाई, 2016 में आम आदमी पार्टी का दामन थामा था। गोम्स ने गोवा प्रशासन में 20 साल से ज्यादा काम किया है। आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गोम्स को गोवा में मुख्यमंत्री पद का अपना उम्मीदवार बनाने की घोषणा की थी। आप में शामिल होने के लिए उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी। उस समय वह आईजी जेल तथा शहरी विकास सचिव थे।

एलविस गोम्स नगर निगम प्रशासन के निदेशक भी रह चुके हैं। वे पर्यटन विभाग के निदेशक और गोवा हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं। पद से इस्तीफा देने से पहले गोम्स और गोवा सरकार के बीच काफी अनबन देखने को मिली। वहीं आम आदमी पार्टी को उम्मीद है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली गोम्स की छवि का फायदा उसे विधानसभा चुनावों में जरूर मिलेगा। गोम्स के लिए केजरीवाल ने भी राज्य में जमकर चुनाव प्रचार किया था।

जमीन आवंटन मामले में दर्ज हुआ था गोम्स के खिलाफ मुकदमा

गोम्स पर जमीन आवंटन के मामले में एसीबी ने छापेमारी की थी और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। हालांकि गोम्स ने उनके खिलाफ लगे सभी आरोपों को राजनी. ति से प्रेरित बताते हुए खारिज किया। उन्होंने गोवा सरकार पर नौकरशाहों के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए जेल आईजी पद से इस्तीफा दे दिया था।

गोवा विधानसभा की 40 सीटों के लिए 4 मार्च 2017 को वोट डाले गए थे। कभी राजनितिक अस्थिरता के लिए परिचित गोवा में 11 लाख 6 हजार वोटर हैं। इस साल गोवा के 85 फीसदी उम्मीदवारों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। जो पिछले विधानसभा चुनाव से दो प्रतिशत ज्यादा था। 2012 में यहां मनोहर पर्रिकर की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी।

गोवा की 40 विधानसभा सीटों के लिए इस बार के चुनावी मैदान में 251 उम्मीदवारों ने अपना भाग्य आजमाया था। 40 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 36 उम्मीदवार उतारे थे, वहीं आम आदमी पार्टी ने 39, कांग्रेस ने 37, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी ने 25 और एनसीपी ने 37 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे।

दूसरों को बदलने का प्रयत्न करने के बजाए स्वयं को बदल लेना कहीं अधिक अच्छा है।

स्वयं एक समस्या बनने के बजाय क्यों न हम दूसरों की समस्याएं हल करने में सहायक बन जाएं

कूड़े के ढेर पर वैशाली

अंसल प्लाजा वैशाली नाला

32 मीटर मेन रोड सिंडिकेट बैंक के सामने

सेक्टर–4 मंदिर के पास

सेक्टर–3 अंसल प्लाजा के पास

अंसल प्लाजा वैशाली स्थित नाले में बहता खतरनाक रासायनिक पदार्थ

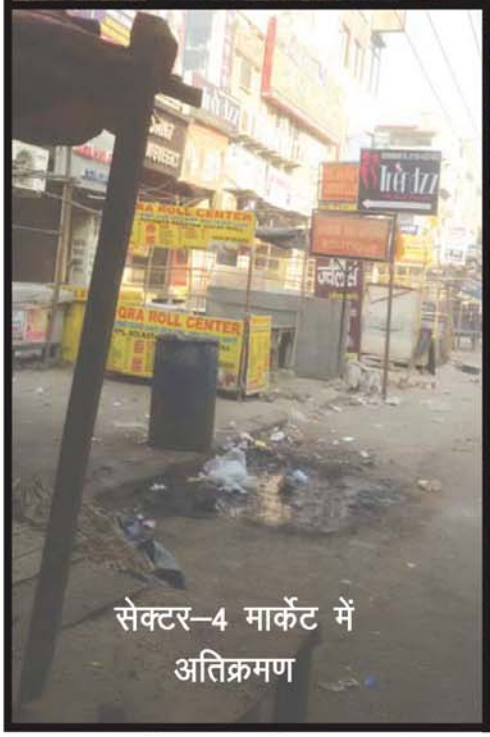
सेक्टर–4 मार्केट में अतिक्रमण

नियम कानून की उड़ रही धज्जियां

गाजियाबाद के वैशाली में नियम कानून की खुलेआम उड़ती धज्जियों के कारण लोगों को हमेशा जानमाल का खतरा बना रहता है। अभी हाल में ही हाईटेंशन तार गिरने से आग लग गई और एक लड़की जल गई। हाईटेंशन तार के आसपास कुछ खतरनाक जोन होता है जिसमें किसी भी तरह का निर्माण एंव अन्य कार्य वर्जित है। लेकिन शासन एवं प्रशासन की मिली भगत से लोग घर बनाकर रह रहे हैं। बड़ी मात्रा में धार्मिक स्थानों का निर्माण कर दिया गया है एक जगह तो पेट्रोल पंप तक बना दिया गया है। यदि कोई घटना घटती है तो भारी जनधन का नुकसान होने की सम्भावना है। दूसरे सड़कों पर अतिक्रमण एवं झुग्गियों के कारण चारों ओर गंदगी है। सरकार किसी बड़ी घटना के इंतजार में है।

सेक्टर–4 वैशाली मार्केट में आरके टावर के सामने जलता पॉलीथिन

हर एक जीवित प्राणी के प्रति दया रखो, घृणा से विनाश होता है

बभनान चीनी मिल कर रही किसानों का शोषण

बभनान के पास बलरामपुर चीनी मिल द्वारा किसानों का शोषण किया जा रहा है। किसानों को समय से गन्ना बेचने की पर्ची नहीं दी जाती है। किसानों के गन्नों की घटतौली की जाती है। यहां पर फर्जी गन्ना किसानों की भरमार है जो किसानों से कम कीमत पर गन्ना खरीद कर मिल को अधिक कीमत पर गन्ना बेच देते हैं। इस क्षेत्र में किसानों के गन्ने को धर्मकांटा पर नहीं तौला जाता है। यही नहीं मिल द्वारा खतरनाक प्रदूषित केमिकल को बिना शोधित किए हुए तालाब एवं नालों में बहा दिया जाता है जिससे दो किलोमीटर के क्षेत्र में भूजल प्रदूषित हो गया है। मकोईया तालाब एंव साथ में लगे तालाबों में प्रदूषित पानी देखा जा सकता है लेकिन शासन, प्रशासन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जांच के नाम पर बिसलेरी पानी के नमूना लेकर क्लीन चिट दे देता है। लोक जागृति द्वारा इस संबंध में शिकायत कर चुका है लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। बभनान के आस पास लोगों को भयंकर बदबू एवं सांस की बीमारी के साथ जहरीली रासायनिक पदार्थ मिला पानी पीने से लोगों एवं जानवरों की मौत भी हो रही है। यदि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समय रहते उचित कार्यवाही नहीं की तो इस क्षेत्र की जमीनें बंजर और भू जल भयंकर प्रदूषित हो जाएगा जिसके कारण लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। वैसे भी आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में लोगों की आयु सबसे कम है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री चुनाव भाषण में कर चुके हैं। इस संबंध में किसी के पास कोई और जानकारी है तो हमें lokjagriti@gmail.com पर मेल कर सकते हैं।

भ्रष्टाचार नापने का पैमाना

मोदी जी व केजरीवाल दोनों भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते हैं लेकिन यह खत्म हुआ है कि नहीं इसका पता आप स्वयं लगा सकते हैं दिल्ली के किसी भी कोने में जाकर रोड किनारे किसी दुकानदार से पूंछे कि यहां ठेला या दुकान लगाने के लिए पुलिस को कुछ देते हो कि नहीं वह आप को बता देगा कि महीना बंधा हुआ है यानी केंद्र के तहत आने वाली पुलिस की ईमानदारी आप स्वयं नाप सकते हैं। इसी तरह से गाजियाबाद केविकास प्राधिकरण के क्षेत्र वैशाली, इंदिरापुरम इत्यादि में यदि आप ईंट सीमेंट मंगाते हैं तो ईंट सिमेंट बाद में आता है जीडीए के लोग पहले आ जाते हैं। हिसाब किताब करने और इस क्षेत्र में अवैध निर्माण का जाल सा बिछ गया है। इसी तरह से इन क्षेत्रों में समरसिबल सीवर लगाने के लिए नगर निगम से एनओसी लेना होता है लेकिन एनओसी के नाम पर सिर्फ पुलिस जेब भर रही है। आप कहीं सिर्फ रोड किनारे एक कुर्सी रख कर खड़े हो जाइए पुलिस आ जाएगी वहीं सड़कों पर अवैध दुकानें, खोखे खुले हुए हैं इससे आप ईमानदारी का नाप सकते हैं। दिल्ली के किसी भी सबरजिस्ट्रार ऑफिस में बिना पैसे दिए प्रापर्टी की सर्टिफाइड कॉपी नहीं निकाल सकते। इंसपेक्शन के नाम पर भी कटने वाली पर्ची में भी घोटाले हो रहे हैं।

धन्यवाद, लोकतंत्र जिंदाबाद!।

उत्तर प्रदेश समेत चार राज्यों में बीजेपी की बंपर जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लाखों कार्यकर्ताओं को दिया है। मोदी ने ट्वीट कर कहा है, मैं बीजेपी के कार्यकताओं को सैल्यूट करता हूं। उन्होंने ग्रासरूट कड़ी मेहनत की और जनता का विश्वास जीता।

एक अन्य ट्वीट में पीएम मोदी ने कहा कि अमित शाह, पार्टी कार्यालय के पदाधिकारियों और राज्य यूनिट के कार्यकर्ताओं ने पार्टी को नई ऊंचाईयों पर पहुंचाया। इसके लिए उन्हें बधाई।

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी को जीत के लिए प्रधानमंत्री को बधाई दी है। जवाब में पीएम मोदी ने लिखा है, धन्यवाद, लोकतंत्र जिंदाबाद!।

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमें जब भी मौका मिला हमने देश के कल्याण के लिए काम किया, हम 125 करोड़ भारतीयों की ताकत में यकीन करते हैं। इससे पहले पीएम ने कहा कि बीजेपी को समाज के सभी वर्गों का समर्थन मिला है। भारी संख्या में युवाओं ने भी हम पर विश्वास जताया है।पंजाब चुनाव परिणाम पर पीएम ने ट्वीट किया, पंजाब की जनता ने अकाली दल और बीजेपी को 10 साल तक सेवा का मौका दिया, इसके लिए शुक्रिया। पीएम ने कहा, उत्तराखंड की जीत बेहद खास है। देवभूमि के लोगों का आभार। मैं विश्वास दिलाता हूं कि भाजपा पूरी तत्परता और कमर्ठता से लोगों की सेवा करेगी। पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों के बारे में लिखा, 'काशी के सांसद के रूप में काशी की जनता का अटूट विश्वास और अपार प्रेम पाकर मैं आज अभिभूत हूं। काशी के लोगों को शत–शत नमन।' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'मैं उत्तर प्रदेश की जनता को हृदय से धन्यवाद देता हूं। भाजपा की ये ऐतिहासिक जीत विकास और सुशासन की जीत है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब में कांग्रेस की जीत के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह को बधाई दी। उन्होंने उन्हें जन्मदिन पर मिली इस जीत के लिए भी बधाई दी। मालूम हो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी को तीन चौथाई बहुमत मिला है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में करीब 324 सीटें गई हैं। गोवा और मणिपुर में भी बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में है।

साभार : इंटरनेट

'शपथ पत्र' एनओसी के भरोसे देश

संतोष मिश्रा

हमारा देश "शपथ पत्र" एवं एनओसी के सहारे चल रहा है। किसी भी व्यक्ति से किसी भी तरह का "शपथ पत्र" ले लो वह दे देगा चाहे सही हो या गलत। अदालतों में एक ही बात पर दोनों पक्ष दो तरह का "शपथ पत्र" देते हैं तो जाहिर है कि एक ही आदमी का "शपथ पत्र" सही होगा दूसरे का गलत।

अभी हमने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन विभाग के इंजीनियर से जानना चाहा कि जब उत्तर प्रदेश वन नीति में पूर्णतः प्रमाण पत्र तभी दिया जाएगा जब उत्तर प्रदेश वन नीति के अनुसार पेड़ लगाए गए हों। किन्तु बहुत सारे मॉल, बिल्डिंग जो प्रथम दृष्टया देखने से लगता है कि उसका पालन नहीं किया है तो आपने पूर्णतः प्रमाण पत्र कैसे दे दिया तो इंजीनियर महोदय ने बताया कि हम "शपथ पत्र" ले लेते हैं कि उत्तर प्रदेश वन नीति के अनुसार पेड़ लगा दिए गए हैं और इस आधार पर पूर्णतः प्रमाण पत्र दे देते हैं। अब जो व्यक्ति गलत "शपथ पत्र" दिया है उसके ऊपर मैं कोई कार्यवाहीं नहीं करुंगा न्यायालय इस पर उचित कार्यवाही करेगी। इसके अलावा अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश वन नीति की कोई जानकारी भी नहीं है। सिर्फ कागजों में कापी पेस्ट होता चला आ रहा है। वैशाली के कई माल, ग्रुप हाऊसिंग सोसायटी में एक भी पेड़ नहीं लगा हैं जो लगे भी गमले में लगे हैं। जब शत–प्रतिशत सीमेंटेड, कंक्रीट बना दिया गया है तो पेड़ तो वहां लग नहीं सकते इसके लिए जमीन चाहिए होती है। इसी तरह से एनओसी का हाल है। हमारे देश में कई कामों के लिए एनओसी लेनी होती है। एनओसी का भी मतलब होता है "नोट पानी देना"। बिल्डिंग बनाते समय फायर एनओसी और अन्य तरह की एनओसी की जरुरत होती है जबकि बिल्डिंग बन जाने के बाद फायर विभाग को एनओसी देनी चाहिए कि बिल्डिंग फायर से सुरक्षित है और आग लगने पर उसे वह काबू कर लेगा यानी फायर ब्रिगेड की गाड़ी बिल्डिंग के चारों ओर घूम सकेगी और आग बुझाई जा सकती है लेकिन कई ऐसी बड़ी–बड़ी बिल्डिंग है जिसमें कई पब्लिक उपयोगी संस्थाएं चल रही हैं लेकिन उसमें फायर एनओसी नहीं है। वैशाली में मेट्रो के पास गौड़ की बिल्डिंग में फायर एनओसी नहीं है। कोर्ट एवं सरकारें उपहार कांड का इंतजार करती, जब लोगों की मौत हो जाती है तब कार्यवाही चालू करती है। फायर ब्रिगेड की तरह आग लगने पर आग बुझाना, लोगों के मरने एवं घटना हो जाने के बाद कार्यवाही।

आदमी हवा के बिना पांच मिनट जिंदा नहीं रह सकता है लेकिन उसी को नष्ट करने में लगा हुआ है। गाजियाबाद के वैशाली, इंदिरापुरम एवं अन्य जगहों पर पेड़ पौधे नहीं है और जो कुछ पेड़ बचे हैं उन्हें "शपथ पत्र" देकर काट डाला जा रहा है कि मैं इसकी जगह इतने पेड़ अन्यत्र लगाउंगा लेकिन काटने के बाद न कहीं पेड़ लगता है सब केवल काम पूरा कर लेते हैं। बाद में न्यायालय को कहना पड़ता है कि दिल्ली गैस चेंबर बन गई है। उसके पहले सब कुम्भकरणी नींद में सोए रहते हैं। हमारे जैसे जागरुक यदि न्यायालय में जाते हैं तो वहां जलेबी के जाल में उलझा कर रख दिया जाता है और वैसे ही न्यायालय की सुनता कौन है– जैसे, इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक आदेश एसपी बनर्जी के केस में कहा है कि जितनी कम्पाउंडिंग यूनिट है उससे अधिक निर्माण को कोर्ट की अवमानना माना जाएगा लेकिन यह सिर्फ नक्शे पर ही उपयोग होता है। रजिस्ट्रार रजिस्ट्री कर रहा है, बैंक लोन कर रहा है, इंजीनियर अपनी हिस्सेदारी लेकर बनवा रहे हैं सब तो चल रहा है इसी की आड़ में कुछ ब्लैकमेलरों का काम भी चल रहा है, जीडीए में शिकायत के नाम पर धंधा कर रहे हैं। सब तो मजे में हैं फिर काहे का नियम कानून। भारत की उच्चतम न्यायालय ने कई महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं कि पार्क के लिए छोड़ी गई जमीन में और कोई गतिविधि नहीं हो सकती लेकिन प्राधिकरण पार्क को बेच देता है या फिर सीवर टैंक बना देता है लेकिन कोई कोर्ट की अवमानना नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि सार्वजनिक एवं सरकारी जमीन पर यदि कब्जा होता है तो इसके लिए जिला प्रशासन सीधे जिम्मेदार होगा लेकिन गाजियाबाद के इंदिरापुरम, वसुंधरा के ग्रीन बेल्ट पर इस तरह से कब्जा किया गया है कि अब उच्चतम न्यायालय क्या अंतरराष्ट्रीय न्यायालय भी नहीं खाली करा सकता है। सिवाय कुछ आर्थिक दण्ड लगाकर खानापूर्ति के जिस तरह से दिल्ली में बड़ी गाड़ियों के रोक को उच्चतम न्यायालय द्वारा कुछ आर्थिक दण्ड, शुल्क इत्यादि के साथ अनुमति देने का मामला रहा हो। यहां तो तू डाल डाल मैं पात पात वाला खेल चल रहा है।

मतलब
तू डाल–डाल मैं पात–पात

गलतफहमी प्रेमपूर्ण व शुद्ध विचारों से तथा समुचित समय पर सही ज्ञान देकर दूर की जा सकती है।

अमल में कैसे आएगी स्वास्थ्य नीति

पारुल भारद्वाज

बड़ी उम्मीदों के साथ लाई जा रही केंद्र सरकार की हेल्थ पॉलिसी में कहने को तो बड़ी–बड़ी बातें हैं लेकिन इससे देश का स्वास्थ्य ढांचा सुधरने की उम्मीद कम ही है। इस नीति के मुताबिक हर भारतवासी स्वास्थ्य लाभ का हकदार है, लेकिन शिक्षा के अधिकार की तरह स्वास्थ्य को लोगों का मौलिक अधिकार नहीं बनाया जा सकता। सरकार का इरादा स्वास्थ्य पर जीडीपी का 2.5 फीसदी खर्च करने का है। अभी यह खर्च जीडीपी का 1.04 प्रतिशत है। सरकार का लक्ष्य है कि देश के 80 फीसदी लोगों का इलाज सरकारी अस्पताल में पूरी तरह मुफ्त हो, जिसमें दवा और जांच भी शामिल है। हेल्थ पॉलिसी में सभी मरीजों को बीमा का लाभ देने का भी प्रावधान है। उन्हें प्राइवेट अस्पताल में भी इलाज करवाने की छूट मिलेगी। स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत निजी अस्पतालों को ऐसे इलाज के लिए तय रकम दी जाएगी। जिला अस्पताल और इससे ऊपर के अस्पतालों को सरकारी नियंत्रण से अलग किया जाएगा और इसे पब्लिक–प्राइवेट पार्टनरशिप में शामिल किया जाएगा। भारत जैसे देश में, जहां कुपोषण के कारण पांच साल से कम उम्र के करीब दस लाख बच्चों की हर साल मृत्यु हो जाती हो, हेल्थ सेक्टर में उठाया गया हर कदम अपर्याप्त ही लगता है। भारत की चुनौतियों को देखते हुए हेल्थ के लिए जीडीपी की 2.5 फीसदी राशि अब भी बहुत कम है। ब्रिक्स देशों में ब्राजील अपनी जीडीपी का 3.8 प्रतिशत, रूस 3. 7 प्रतिशत और चीन 3.1 प्रतिशत

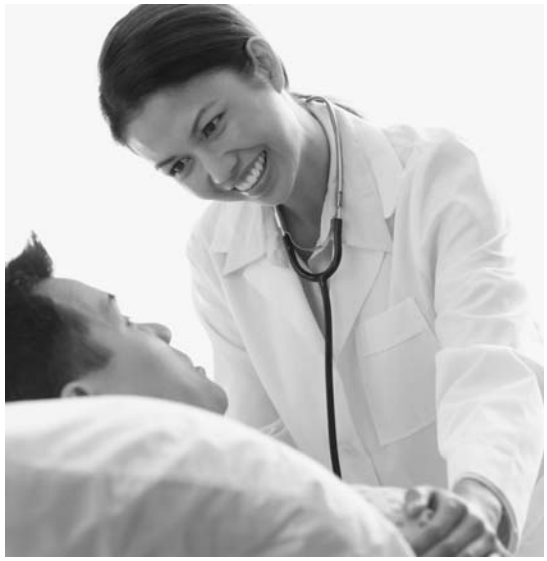

सार्वजनिक स्वास्थ्य पर खर्च करते हैं। फिर भी कहना होगा कि केंद्र सरकार ने एक कदम आगे की ओर जरूर बढ़ाया है। लेकिन यहां सिर्फ अच्छे इरादों से काम नहीं चलने वाला। असल चुनौती स्वास्थ्य नीति को जमीन पर उतारने की है। यह तभी कारगर हो पाएगी जब राज्य सरकारें इसे गंभीरता से लें। स्वास्थ्य राज्य का विषय है और राज्य अपनी प्राथमिकता के आधार पर इसका बजट रखते हैं। जैसे, यूपी जैसा बड़ा राज्य सबसे कम खर्च हेल्थ पर ही करता है। जबकि गोवा, जहां की आबादी उत्तर प्रदेश की आबादी के 1 फीसदी से भी कम है, अपने नागरिकों के स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति पांच गुना ज्यादा खर्च करता है। योजना आयोग के भंग होने के बाद राज्य सरकारों की भूमिका और बढ़ गई है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं में कटौती हुई है और विकास मद का ज्यादा बड़ा हिस्सा राज्यों को हस्तांरित हुआ है। जाहिर है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत कुछ राज्यों पर निर्भर करता है। अगर इस क्षेत्र में आमूल बदलाव करना है तो इसे समवर्ती सूची में लाने पर क्यों नहीं विचार किया जाता। स्वास्थ्य में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि जनता का एक बड़ा तबका निजी क्षेत्र का लाभ लेने की स्थिति में नहीं है। आशा है, केंद्र सरकार राज्यों से बेहतर तालमेल बनाकर स्वास्थ्य के मामले में भारत को अभी की फिसड्डी स्थिति से बाहर ले आएगी।

संक्रमण के खिलाफ भी होता है अश्वगंधा का इस्तेमाल

अश्वगंधा सैकड़ों वर्ष से एक हर्बल उपचार के रूप में उपयोग में लाया जाता है। न केवल भारत में, बल्कि नेटिव अमे. रिकिन और अफ्रीकन भी सूजन और बुखार का इलाज और संक्रमण के खिलाफ संरक्षण के रूप में इसका उपयोग कर रहे है। अश्वगंधा भारतीय जिनसेंग (औषधीय पौधा जो दक्षिण एशिया और उत्तर अमेरिका में पाया जाता है) के रूप में जाना जाता है और इसका उपयोग आयुर्वेदिक चिकित्सा में किया जाता है जैसे कि एशियन जिनसेंग पारंपरिक चीनी चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। अश्वगंधा चाय पौधो की जड़ों और पत्तियों से बनी होती है और स्वास्थ्य लाभ के लिए भी उपयोग में लाई जाती है। यह चाय आसानी से एक पोने घंटे के लिए पानी में सूखी जड़ी बूटी को उबालने और फिर इसको छानने के द्वारा घर पर आसानी से बनाई जा सकती है। पौधे की जड़ बड़े पैमाने पर वजन में कम से कम तीन ग्राम होनी चाहिए, और यह मात्रा तीन से चार कप चाय बनाने के लिए चाहिए। क्या है अश्वगंधा टमाटर के रूप में एक ही संयंत्र परिवार से एक झाड़ी (पौधा) है। इसमें फ्लेवोनॉइड और एंटीऑक्सीडेंट की तरह कई लाभकारी तत्व है। अनुसंधान से पता चलता है कि यह मस्तिष्क में न्यूरोलॉजिकल ट्रांसमिशन में सुधार लाने में मदद करता है। स्कूल जाने वाले बच्चों नें याददाश्त में सुधार आने जैसे लाभो के बारे में कहा है और हर सुबह नियमित रूप से अश्वगंधा चाय के सेवन द्वारा ज्ञान को स्वीकार किया है।

एजेंसी

परमात्मा को अपना साथी बना लें तो चिन्ता की रेखाएं चेहरे पर नहीं आएंगी।

प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है एलोवेरा

एलोवेरा को घृतकुमारी भी कहते हैं। एक छोटा सा कटीला पौधा होता है जिसकी पत्तियों में ढेर सारा तरल पदार्थ भरा होता है। इसमें कई प्रकार के प्रोटीन और विटामिन पाए जाते हैं, इसलिए यह हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। एलोवेरा औषधीय गुणों से भरपूर होता है। एलोवेरा का नियमित इस्तेमाल करके आप फिट रह सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि एलोवेरा के क्या–क्या फायदे हैं और इसका उपयोग किस–किस तरह से किया जा सकता है।

एलोवेरा हमारे शरीर में खून की कमी को दूर करके रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है।

एलोवेरा हमारे शरीर की अंदरूनी सफाई करता है और शरीर को रोगाणु से मुक्त रखने में मदद करता है। यह हमारे शरीर की नस, नाड़ियों आदि की सफाई करता है।

त्वचा की देखभाल और बालों की मजबूती व बालों की समस्या से निजात पाने के लिए एलोवेरा संजीवनी का काम करती है।

एलोवेरा का जूस पीने से त्वचा की नमी बरकरार रहती है। और त्वचा चमकदार दिखती है। यह त्वचा के लचीलेपन को बढ़ाकर त्वचा को खूबसूरत बनाता है।

एलोवेरा का जूस पीने से त्वचा की खराबी, मुहांसे, रूखी त्वचा, झुर्रियाँ, चेहरे के दाग–धब्बे, आँखों के काले घेरे दूर होते हैं।

एलोवेरा का उपयोग कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। एलोवेरा जूस खून को शुद्ध करता है और हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा करता है। यह शरीर में ब्लड सेल्स की संख्या बढ़ाता है।

यह दिल से सम्बन्धित समस्याओं, जोड़ों के दर्द, मधुमेह, यूरिन की समस्या, शरीर में जमा विषैले पदार्थ आदि को खत्म करने में मददगार है।

इसका नियमित उपयोग करके लंबी उम्र तक स्वस्थ रहा जा सकता है।

हर दिन एक ग्लास एलोवेरा जूस पीने से वजन घट जाता है।

एलोवेरा जूस दांतों को साफ और रोगाणुमुक्त रखता है। एलोवेरा जूस को माउथ फ्रेशनर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एलोवेरा के जूस को मुंह में भरने से छाले और बहने वाले खून को रोका जा सकता है।

एलोवेरा का इस्तेमाल करने से बाल झड़ने की समस्या कम हो जाती है।आप फेसवास के रूप में भी इसका उपयोग कर सकते हैं।

एलोवेरा के लिक्विड में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर सिर में लगाने से सिर दर्द में आराम पहुँचता है।एलोवेरा का जूस हर दिन पीने से कब्ज से राहत मिलती है।एलोवेरा का जूस और आँवला के जूस को मिलाकर पीने से मधुमेह में लाभ पहुँचता है।फटी एड़ियों में एलोवेरा जेल लगाने से लाभ पहुँचता है।

एलोवेरा का जूस पीने से पीलिया में भी फायदा पहुँचता है।

साभार : इंटरनेट

बीसीआई के खिलाफ लामबंद हुए वकील

नई दिल्ली। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के चेयरमेन श्री मनन कुमार मिश्रा जी चर्चा का विषय बने हुए है क्यों कि इन्होंने हाल ही में अपनी एक सिफारिश लॉ कमीशन को भेज कर पूरे देश में बवाल खड़ा कर दिया है, जिसमे वकीलों के लिए हड़ताल को बैन करने व वकीलों पर लाखों का जुर्माने, व लाइसेंस सस्पेंड करने जैसी सिफारिशें हैं। जिससे वकील के संवैधानिक अधिकारों का अतिक्रमण झलकता है, व वकीलों को पंगु या उन की संगठित ताकत को तोड़ने का प्रयास जैसा है। कुछ समय पहले एक अंग्रेजी अखबार की एक खबर के अनुसार मनन मिश्रा जी ने भारत के मुख्य न्यायधीश जगदीश सिंह खेहर को सूचित किया कि देश में 40 वकील फर्जी हैं, जो वकील हड़ताल करते हैं या उसका हिस्सा बनते हैं वे पूर्णतयः फर्जी हैं वे वकील नहीं है। मेरा संस्था द्वारा मनन मिश्र से कुछ सवाल है कि

1. क्या आपने कभी कोई हड़ताल नहीं की या किसी हड़ताल का हिस्सा नहीं रहे। इस तरह की सिफारिशों से क्या वकील आहत नहीं होते ये पद की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाता?
2. सर्व प्रथम आप 'फर्जी वकील' शब्द को परिभाषित करें।
3. 'फर्जी वकील' कौन है ? कहाँ से आते है? और बनते कैसे है?
4. क्या फर्जी वकील किसी कॉलेज से LLB नहीं करते? LLB करने उपरांत राज्य बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं कराते? या ऑल इंडिया बार एग्जाम नहीं देते? इन सभी पड़ाव को पार करने के बाद भी 'फर्जी वकील'?
5. आज जगह–जगह LLB के हजारो कॉलेज खुले हैं जो गारंटी से LLB करा रहे है इन कॉलेज को BCI से मान्यता कैसे मिल जाती है जिसमें बच्चे को बिना जाये अटेंडेंस लगा दी जाती है क्या इन कार्यों को रोकने में BCI की कुछ भूमिका नहीं ?
6. जब फर्जी वकील बनना गलत है तो फर्जी वकील बनाना भी गलत है, BCI क्यू कुछ रूल नहीं बनाती जिस से 'फर्जी वकील' जैसे कलंक से बचा जा सके?
7. कॉलेज स्तर पर वेरिफिकेशन रूल क्यों नहीं लाया गया? जैसे चिंगारी ही आग का रूप धारण करती है, जबकि चिंगारी को बुझाना आसान है और आग को बुझाने कठिन अर्थात कॉलेजों की प्राथमिक तौर पर जिम्मेदारी सुनिशित करे जिस से 'फर्जी वकील' पैदा होना असंभव हो सके?
8. आप ने अपने कार्य काल में कितने कॉलेज को लाइसेंस दिया गया?

मन के संकल्पों को बीच–बीच में रोकने का अभ्यास कर लें तो थकावट नहीं होगी।

नीम के गुण

नीम का पत्ता इस धरती पर पाया जाने वाला सबसे विविध गुणों वाला पत्ता है। शरीर की सफाई में इसके खास फायदे हैं। जो लोग पश्चिम से आए हैं, भारत में आपको सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि आपको पेट के इंफेक्शन हो जाते हैं। कोई भी चीज, जो भारतीयों के लिए बहुत बढ़िया और स्वादिष्ट होगी, आपको शौचालय के चक्कर लगवा सकता है क्योंकि यह दुनिया बैक्टीरिया से भरी हुई है। यह शरीर बैक्टीरिया से भरा हुआ है। एक सामान्य आकार के शरीर में, करीब दस ट्रिलियन मानव को. शिकाएं होती हैं लेकिन 100 ट्रिलियन से अधिक बैक्टीरिया होते हैं। आप दस में एक की दर से अल्पसंख्यक हैं। आपके अंदर इतने जीवों का निवास है जितनी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इनमें से अधिकांश बैक्टीरिया हमारे लिए मददगार होते हैं। उनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, लेकिन उनमें से कुछ हमारे लिए समस्या उत्पन्नं कर सकते हैं। अगर आप नीम का सेवन करें, तो वह आंत में समस्या उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है।

नीम के बहुत से अविश्वसनीय फायदे हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि वह कैंसर उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं को खत्म कर देता है। हम सब के शरीर में कैंसर उत्पन्न करने वाली कोशिकाएं होती हैं लेकिन वे अव्यवस्थित होती हैं, वे पूरे शरीर में बिखरी होती हैं। छोटा–मोटा अपराध अगर संगठित अपराध बन जाए तो यह गंभीर समस्या हो जाती है। हर शहर में हर कहीं छोटे–मोटे अपराधी होते हैं। वे यहां–वहां लोगों की जेब काटेंगे, यह कोई समस्या की बात नहीं है। लेकिन अगर पचास जेबकतरे एक शहर में संगठित हो जाएं, तो अचानक शहर का सारा माहौल बदल जाएगा। ये पचास लोग साथ मिलकर ऐसी चीजें कर सकते हैं कि आपके लिए सड़क पर निकलना खतरनाक हो जाएगा। शरीर में यही सब हो रहा है। कैंसर उत्पन्न करने वाली कोशिकाएं इधर–उधर दौड़ रही हैं।

अगर वे अपने आप यूं ही आवारागर्दी करते हैं तो इसमें कोई समस्या नहीं है। अगर वे एक जगह मिलकर हमला करते हैं, तब समस्या है। इसके लिए उन्हें तोड़ते रहना होगा, यहां–वहां कुछ कोशिकाओं को मारना होगा, इससे पहले कि वे संगठित हो पाएं। रोजाना नीम का सेवन यही काम करता है, यह शरीर में कैंसर पैदा करने वाली कोशिकाओं को सीमित रखता है, जहां वे शरीर के खिलाफ इकट्ठा नहीं हो पाती। इसलिए नीम का सेवन बहुत महत्वपूर्ण है।

नीम बैक्टीरिया की संख्या को कम करता है अगर आप नीम का सेवन करें, तो हो सकता है कि मच्छर भी आपको न काटें। अगर आप नहाने से ठीक पहले नीम का पेस्ट अपने ऊपर लगाएं, थोड़ी देर उसे सूखने दें और फिर पानी से धो लें, तो यह अपने आप में एक क्लींजर है, बाहर का सारा बैक्टीरिया नष्ट हो जाएगा। या आप नीम के कुछ पत्ते ले कर उन्हें पानी में डाल लें, रात भर छोड़ दें और उससे स्नाान करें।

यह महत्वपूर्ण है कि हमारे शरीर में बैक्टीरिया की बहुतायत न हो। बैक्टीरिया के सक्रिय हुए बिना आप जीवित नहीं रह सकते। लेकिन अगर बैक्टीरिया की बहुतायत हो गई, तो आप बीमार महसूस करेंगे क्योंकि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली उनसे निपटने में बहुत ऊर्जा खर्च करती है। नीम का अलग–अलग रूपों में इस्तेमाल करते हुए, आप बैक्टीरिया को इतना सीमित कर सकते हैं कि आपको उसे संभालने में शरीर की ऊर्जा खर्च न करनी पड़े।

हल्दी एक ऐसा तत्व है जो न सिर्फ शरीर के लिए लाभदायक है, बल्कि ऊर्जा तंत्र के लिए भी कारगर है। यह रक्त, शरीर और ऊर्जा तंत्र में एक खास शुद्धिकरण प्रक्रिया लाता है। आप बाहर से भी इसे शुद्धिकरण के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ एक चुटकी हल्दी लेकर उसे बाल्टी भर पानी में डालकर वह पानी अपने शरीर पर उड़ेलें। आप देखेंगे कि इससे शरीर ऊर्जावान और कांतिमय हो जाएगा। हल्दी के नियमित सेवन से रक्त शुद्ध रहता है और रक्त का रसायन एक संतुलन में रहता है। यह रक्त का शुद्धिकरण करता है और आपकी ऊर्जा में एक चमक लाता है।

साभार : इंटरनेट

यदि आप दूसरों की कमजोरियां अपने मन में रखते हैं तो शीघ्र ही वे आपका अंग बन जाएंगी।

लोक जागृति द्वारा प्रतियोगी बच्चों को पुरस्कृत करते संस्था संस्थापक संतोष मिश्रा व अन्य।

कार्यक्रम के दौरान मौजूद संस्था के सदस्य एवं पदाधिकारीगण।

लोक जागृति द्वारा आयोजित भंडारा देते संस्था के पदाधिकारी।

लोक जागृति द्वारा आयोजित भंडारे के लिए लगी लोगों की लाइन।

RNI NO.UPHIN/2011/39809

लोक जागृति पत्रिका के विशिष्ट अंक